● वर्ष-5

● अंक-208

रायपुर, शुक्रवार
17 अप्रैल 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के ...

महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा जारी

लोकसभा में परिसीमन से संबंधित तीन विधेयक पेश, आज होगा निर्णय

नईदिल्ली। विशेष संसदीय सत्र के दौरान तीन महत्वपूर्ण विधेयकों पर 15 से 18 घंटे तक चर्चा शुरू हुई और शुक्रवार को शाम 4 बजे मतदान निर्धारित है। सदन में बोलते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इन तीनों विधेयकों पर 15-18 घंटे तक चर्चा होगी। इन विधेयकों पर मतदान आज शाम 4 बजे होगा।

केंद्र सरकार ने विपक्ष के कड़े विरोध के बीच लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से संबंधित तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 'संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026' और 'परिसीमन विधेयक, 2026' पेश किए, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' पेश किया। संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के पक्ष में 251 वोट पड़े, जबकि 185 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया। सरकार का कहना है कि महिला आरक्षण को सही तरीके से लागू करने के लिए ये तीनों विधेयक एक साथ लाना जरूरी है।

कांग्रेस, सपा और द्रमुक समेत कई विपक्षी दलों ने इन विधेयकों को असंवैधानिक बताया है। कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने सवाल उठाया कि जब 2023 में ही महिला आरक्षण बिल पास हो गया था, तो उसे तभी लागू क्यों नहीं किया गया? उन्होंने सरकार पर 2029 के चुनावों से डरने का आरोप लगाया। वहीं, अखिलेश यादव और अन्य नेताओं ने कहा कि जनगणना के बिना परिसीमन करना संविधान की भावना के खिलाफ है। विपक्षी नेताओं का मानना है कि इन बदलावों से देश के

महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री मोदी

जिसने नारी शक्ति का विरोध किया, उसका बुरा हाल हुआ

नई दिल्ली। लोकसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पर जारी चर्चा में शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में जब जब चुनाव आया है उसमें महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस-जिसने विरोध किया है। उसका हाल बुरे से बुरा हुआ है। उन्हें कभी माफी नहीं मिली।

उन्होंने कहा कि इसलिए जिन्हें भी इसमें राजनीति की बू आ रही है, वे खुद के परिणामों को देख लें। इसमें फायदा है, जो नुकसान हो रहा है उससे बच सकते है। इसलिए इस बिल को राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारी नीयत की खोट को देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। इसके पहले अखिलेश यादव ने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा वे उसके मान सम्मान को कैसे रख सकते है। वहीं चर्चा में शामिल होकर पीएम मोदी ने कहा कि यहां कुछ लोगों को लगता है, इसमें कहीं न कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। इसका अगर विरोध करते हैं, तब स्वभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा। अगर साथ चलते हैं, तब किसी को भी नहीं होगा। फिर अलग पहलू हो जाता है। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए जैसे ही पारित हो जाए, तब मैं विज्ञापन देकर सभी का धन्यवाद देने तैयार हूं। सबकी फोटो छपवा देने वाला हूं। ले लो जी क्रेडिट। इतना ही नहीं पीएम मोदी ने कहा कि अगर गांरटी शब्द चाहिए, तब मैं वह शब्द भी उपयोग करता हूं, वादा की बात करते हो, तब उसका भी इस्तेमाल करता हूं। तमिल में कोई शब्द हो, तब मैं उस शब्द को भी कहता हूँ। क्योंकि जब नीयत साफ है, तब शब्दों का खेल करने की जरूरत नहीं है। इस दौरान विपक्ष पर तंज कंसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहां परंपरा है कि अच्छे काम में किसी की नजर न लगे इसके लिए काला टीका लगाते हैं, इसलिए मैं आपका (डीएमके) धन्यवाद करता हूं।

दरअसल, पीएम मोदी ने डीएमके का नाम लिए बिना जिक्र किया।

3 अहम बिल पर बहस 12 घंटे तक चलेगी

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आगे कहा कि बहस 12 घंटे तक चलेगी और उन्होंने तर्क दिया कि स्पीकर को चर्चा का समय बढ़ाने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने पुष्टि की कि मतदान अगले दिन होगा। रिजिजू ने कहा कि चर्चा 12 घंटे तक चलेगी। स्पीकर को चर्चा का समय बढ़ाने का अधिकार होना चाहिए। विधेयकों पर मतदान आज होगा। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने तीनों विधेयकों पर एक साथ विचार किए जाने पर आपत्ति जताते हुए इसे संसदीय प्रक्रिया का उल्लंघन बताया और इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर संविधान संशोधन विधेयक के खारिज होने की ही संभावना है तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का क्या औचित्य है।

किसी राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा : मेघवाल

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधी ऐतिहासिक निर्णय को लागू करने का समय आ चुका है। उन्होंने परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक के साथ-साथ संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा शुरू की। इसके पहले केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक को पारित करने के प्रस्ताव पर प्रक्रिया नियमों के नियम 66 के प्रावधान को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि ये विधेयक संविधान संशोधन विधेयक, 2026 पर निर्भर हैं। इसके बाद सदन में मतदान के बाद यह प्रस्ताव पारित हो गया। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित किए गए मतों के अनुसार, 251 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 185 सदस्यों ने इसके विरोध में मतदान किया।प्रस्ताव में बताया गया है कि यह सदन परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार करने और उन्हें पारित करने के प्रस्तावों के संबंध में लोकसभा में कार्य प्रक्रिया एवं संचालन नियमों के नियम 66 के परंतुक को निलंबित करें।

राहुल गांधी ने कहा- वेणुगोपाल का माइक क्या सही है? स्पीकर बोले.....माइक चालू है, आपका ही होता है बंद

संसद के विशेष सत्र के पहले दिन गुरुवार को लोकसभा में उस समय माहौल हल्का-फुल्का लेकिन राजनीतिक रूप से गरम हो गया, जब माइक को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बातचीत ने तंज का रूप ले लिया। घटना के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के माइक को लेकर सवाल उठाया कि क्या उनका माइक ठीक से काम कर रहा है। इसी बीच कुछ सांसदों ने भी कहा कि माइक बंद है।इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुस्कुराते हुए तंज कस दिया—माइक चालू है, आपका ही बंद होता है।उनकी यह टिप्पणी सदन में कई सदस्यों के लिए हंसी का कारण बनी, लेकिन राजनीतिक संकेतों के कारण यह चर्चा का विषय भी बन गई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी विपक्ष की ओर से की गई टिप्पणियों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बिना विधेयक पर विस्तृत चर्चा के उसकी मंशा पर सवाल उठाना उचित नहीं है।

वेदांता पावर प्लांट हादसा

अनिल अग्रवाल समेत 19 पर एफआईआर दर्ज

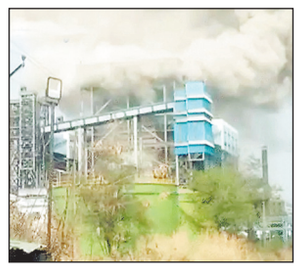

सक्ती। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण हादसे के बाद बड़ी कानूनी कार्रवाई सामने आई है। 14 अप्रैल को हुए बॉयलर ब्लास्ट में अब तक 20 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 घायल अलग-अलग अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल समेत 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस जांच में प्रारंभिक रूप से प्लांट प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। इसी आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106, 289 और 3-5 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इसमें प्लांट हेड देवेंद्र पटेल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

हादसा 14 अप्रैल को वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर ब्लास्ट के कारण हुआ था। इस दुर्घटना में कुल 20 मजदूरों की मौत हो चुकी है। प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार मृतकों में 5 लोग छत्तीसगढ़ के हैं, जबकि 15 मजदूर अन्य राज्यों से संबंधित हैं। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ श्रम कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है।

इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी मुआवजे की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। वहीं कंपनी प्रबंधन ने भी मुआवजे और सहायता की घोषणा की है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के कचहरी चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की कचहरी शाखा के नवीन एवं अत्याधुनिक परिसर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधकप्रभाष कुमार सुबुद्धि, उप महाप्रबंधक श्री रमेश सिन्हा, प्रबंधक अनिल यादव सहित बैंक के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रमुख समाचार

परिसीमन को लेकर महिला आरक्षण को गिराने का प्रयास नहीं होना चाहिए: रिजिजू

नई दिल्ली। संसद में गुरुवार को महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिल पेश किए। इन बिलों में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 2029 से 33फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव है। इसके लिए तीन दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। इससे पहले नारी वंदन शक्ति अधिनियम पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मेरा विश्वास है कि हर पार्टी अपना-अपना पक्ष रखेगी। मुख्य मुद्दा यह है कि महिलाओं को आरक्षण देना। लोकसभा और विधानसभाओं में भारत की महिलाओं को 33फीसदी आरक्षण देना। सामान्य सीट से भी महिलाएं चुनकर आ सकती हैं लेकिन 33फीसदी आरक्षण देने के बाद भारत के लिए यह ऐतिहासिक हो जाएगा। भारत दुनिया में मिसाल कायम करेगा कि हम महिलाओं के लिए कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं। इसका विरोध करने की जरुरत नहीं है। परिसीमन या अन्य विषयों को उठाकर महिला आरक्षण को गिराने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। परिसीमन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है।

ये देश के संघीय ढांचे को नष्ट करेगा: ओवैसी

नई दिल्ली। एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कार्यान्वयन से जुड़े प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों को लेकर केंद्र की आलोचना कर कहा कि इससे भारत की संघीय संरचना कमजोर होगी। लोकसभा के विशेष सत्र में बिल पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख औवेसी ने कहा कि ये विधेयक देश के संघीय ढांचे को नष्ट करेगा। मैं इन विधेयकों के प्रस्तुत किए जाने का कड़ा विरोध करता हूं। उन्होंने साहिर लुधियानवी का एक शेर पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा, एक शहंशाह ने बनवा कर हसीन ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून को लागू करने के उद्देश्य से 3 संशोधन विधेयकों पर चर्चा के साथ शुरू हुआ, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। सप्ताह के आरंभ में, केंद्र ने संविधान विधेयक, 2026 का मसौदा प्रसारित किया।

परिसीमन विधेयक को बताया लोकतंत्र पर कुटिल वार: खड़गे

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इन प्रस्तावों को लोकतंत्र पर कुटिल हमला बताते हुए विपक्ष की ओर से एकजुट विरोध की बात कही। कांग्रेस नेता खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि विपक्ष संसद को महिला आरक्षण के नाम पर पेश किए गए दोषपूर्ण परिसीमन विधेयकों के प्रभाव में नहीं आने देगा। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष इन प्रस्तावों का पूरी ताकत से मुकाबला करेगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब लोकसभा में संविधान संशोधन और परिसीमन से जुड़े तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए हैं। इन विधेयकों में 'संविधान विधेयक 2026' और परिसीमन से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं, जिन्हें सरकार ने महिला आरक्षण व्यवस्था को लागू करने की दिशा में अहम कदम बताया है। विपक्षी दलों जिनमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और द्रमुक प्रमुख रूप से शामिल हैं ने इन विधेयकों को असंवैधानिक बताते हुए प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।

अशोक चक्र पर गाइडलाइंस बनाने की मांग पर सुनवाई से कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पर अशोक चक्र के प्रदर्शन को लेकर गाइडलाइंस बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि इस तरह के मामलों में अत्यधिक भावुक होने के बजाय रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देना ज्यादा जरुरी है।मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि इन बातों को लेकर इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। आपका विचार अच्छा है, आपने अपनी बात रख दी है। अब यह संबंधित अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वे क्या फैसला लेते हैं।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को समाज के लिए कुछ सकारात्मक और रचनात्मक कार्य करने चाहिए, जिससे व्यापक स्तर पर लाभ मिल सके। दरअसल, याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने अशोक चक्र के प्रदर्शन से जुड़ा एक मुद्दा उठाया था।

दिल्ली एयरपोर्ट पर अकासा और स्पाइसजेट के विमान टकराए

नई दिल्ली। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया, जब अकासा एयर और स्पाइसजेट के विमान आपस में टकरा गए। यह घटना 16 अप्रैल को करीब दोपहर 2 बजे एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में हुई।प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अकासा एयर की दिल्ली से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट क्यूपी-1406 पुशबैक के दौरान पार्किंग बे से बाहर निकल रही थी। उसी समय लेह से दिल्ली पहुंचा स्पाइसजेट का बोइंग बी-737-700 विमान टैक्सी वे से गेट की ओर बढ़ रहा था, तभी दोनों विमानों की टक्कर हो गई।हादसे में स्पाइसजेट विमान का राइट विंगलेट क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि अकासा एयर के विमान के लेफ्ट होरिजोंटल स्टेबलाइजर को नुकसान पहुंचा है। टक्कर के बाद मौके पर मौजूद ग्राउंड स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों विमानों में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, घटना के बाद दोनों विमानों को एहतियातन ग्राउंड कर दिया गया है और उन्हें अगली उड़ानों के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा। इस संबंध में अकासा एयर के प्रवक्ता ने बताया कि फ्लाइट क्यूपी-1406 को वापस पार्किंग बे में लाया गया और यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।

नारी-आरक्षण

नये भारत का आधार एवं संभावनाओं का शिखर

ललित गर्ग

नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भारत की राजनीति और समाज में जो नई चेतना उभरकर सामने आई है, वह केवल एक विधायी परिवर्तन का संकेत नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक रूपांतरण एवं नये भारत-निर्माण की संभावनाओं की प्रस्तावना है। निश्चितौर पर भारत अब अपने विकास की धुरी में महिलाओं की सक्रिय और निर्णायक भागीदारी को अनिवार्य मानने लगा है। दशकों से लंबित महिला आरक्षण का मुद्दा केवल संसद के गलियारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह भारतीय समाज की उस अंतर्धारा से जुड़ा रहा है, जिसमें बराबरी, सम्मान और अवसर की मांग निरंतर उठती रही है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह सही कहा कि यह इस सदी के महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। पहले यह अधिनियम नई जनगणना के बाद लागू होना था, पर उसमें देरी के चलते सरकार ने इसे 2011 की जनगणना के आधार पर लागू करने का निर्णय किया। इस पर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई है, पर इस आपत्ति को महत्व देने से अगले लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू करना संभव नहीं होगा, क्योंकि ताजा जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बनने वाले परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने में समय लगता और तब तक 2029 के आम चुनाव हो जाते। इसी कारण इस अधिनियम में संशोधन करने हेतु संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया है। चूंकि यह सत्र विधानसभा चुनावों के बीच बुलाया जा रहा है, इसलिए भी कई विपक्षी दलों को यह कांटों की तरह चुभन दे रहा है।

भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी का इतिहास विरोधाभासों से भरा रहा है। एक ओर देश ने इंदिरा गांधी जैसी सशक्त महिला नेतृत्व को देखा, वहीं दूसरी ओर संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या लंबे समय तक सीमित बनी रही। वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी लगभग 15 प्रतिशत के आसपास है, जो यह बताती है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्तर पर अभी भी एक बड़ा अंतर विद्यमान है। इस संदर्भ में महिला आरक्षण अधिनियम उस अंतर को पाटने का एक संगठित और संरचनात्मक प्रयास है। महत्वपूर्ण यह भी है कि इस अधिनियम को लागू करने के संदर्भ में जनगणना और परिसीमन को लेकर जो विवाद सामने आया है, वह भारतीय लोकतंत्र की जटिलताओं को भी उजागर करता है। सरकार द्वारा 2011 की जनगणना के आधार पर इसे लागू करने का निर्णय एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, क्योंकि नई जनगणना और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया में होने वाली देरी महिला आरक्षण को वर्षों तक टाल सकती थी। विपक्ष की आशंकाएं अपनी जगह पर हैं, परंतु अभी तक उनके समर्थन में ठोस तथ्य सामने नहीं आए हैं।

भारतीय राजनीति में किसी भी बड़े निर्णय को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की परंपरा रही है और महिला आरक्षण भी इससे अछूता नहीं है। विपक्ष द्वारा यह आरोप लगाना कि सरकार इस पहल के माध्यम से राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा है। किन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि लोकतंत्र में लिए जाने वाले अधिकांश निर्णयों के पीछे राजनीतिक गणित काम करता है। प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि निर्णय के पीछे राजनीतिक लाभ है या नहीं, बल्कि यह होना चाहिए कि उसका प्रभाव समाज पर कितना सकारात्मक पड़ता है। यदि महिला आरक्षण से महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है और नीति निर्माण में उनका दृष्टिकोण शामिल होता है, तो यह संपूर्ण समाज के लिए लाभकारी होगा। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। महिलाएं अब केवल मतदाता नहीं रहीं, बल्कि वे एक निर्णायक मतदाता वर्ग के रूप में उभरी हैं। 2019 के आम चुनावों में महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों के लगभग बराबर रही और कई राज्यों में उन्होंने पुरुषों से अधिक मतदान किया। यह परिवर्तन केवल संख्या का नहीं, बल्कि चेतना का संकेत है। महिलाएं अब अपने अधिकारों और हितों के प्रति अधिक सजग हो रही हैं और राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं।

बिलासपुर में एएसआई ने पीड़ित को जड़ा थप्पड़

बिलासपुर। बिलासपुर में अपने केस की जानकारी लेने पहुंचे पीड़ित पर ही एएसआई ने अपना गुस्सा उतार दिया। नाराज एएसआईदिनेश तिवारी ने पीड़ित से बोला कि बड़ा नेता है, तेरा सब नेतागिरी निकाल दूंगा, तुझे जेल भिजवा दूंगा। उसने कनपटी पर 15-20 थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है, जिससे उसका कान सुन्न पड़ गया है। इस मामले की शिकायत पर एसएसपी रजनेश सिंह ने एएसआई दिनेश तिवारी को निलंबित कर दिया है। साथ ही फरियादी की शिकायत पर उसी थाने में एएसआई के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। पूरा मामला रनतपुर थाने का है। रतनपुर के बनियापारा निवासी विनोद जायसवाल 12 अप्रैल को अपने पुराने परिवाद की जानकारी लेने थाने पहुंचा था। दोपहर करीब 2.30 बजे विनोद की मुलाकात एएसआई दिनेश तिवारी से हुई। विनोद ने अपने केस की जानकारी मांगी और जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आग्रह किया। इसी बात पर एएसआई नाराज हो गया और मारपीट शुरू कर दी। विनोद जायसवाल का आरोप है कि, एएसआई ने गाली-गलौज करते हुए 15-20 थप्पड़ जड़ दिए। घटना के समय थाने में बाकी स्टाफ भी मौजूद थे। मारपीट के दौरान एएसआई ने धमकी भी दी कि तू कितना बड़ा नेता है, तेरी नेतागिरी निकाल दूंगा, तुझे जेल भिजवा दूंगा। इस मामले में जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के एवज में एएसआई पर पैसे मांगने के भी आरोप लग रहे हैं।

धमतरी में सामूहिक विवाह, 63 जोड़ों ने लिए फेरे

धमतरी। धमतरी में स्थित गंगरेल बांध के पास माँ अंगारमोती प्रांगण में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत एक सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। इस दो दिवसीय आयोजन में कुल 63 जोड़ों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार फेरे लिए और नवदाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। यह सामूहिक विवाह आदिवासी समाज द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग पांच जिलों के दूल्हा-दुल्हन शामिल हुए। कार्यक्रम के पहले दिन, आदिवासी परंपरा के अनुसार गैता पुजारी द्वारा पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद, दूसरे दिन 63 मंडप एक साथ सजाए गए और सभी जोड़ों ने एक ही समय पर विवाह की रस्में पूरी कीं।

मुठभेड़ में मारी गई नक्सली लीडर रूपी को शहीदी विदाई

जगदलपुर। कांकेर के जंगलों में हुई सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारी गई नक्सली कमांडर रूपी का अंतिम संस्कार विवादों में घिर गया है। रूपी का तेलंगाना के मेडक जिले में अंतिम संस्कार किया गया।

इस दौरान कुछ लोग लाल झंडे लेकर नाचते एक शहीद के तौर पर 'रूपी' को अंतिम विदाई देते हुए विवादित 'हिडमा गाना' गाते नजर आ रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। बता दें कि सुरक्षा बलों ने 13 अप्रैल को कांकेर जिले के छोटेबेठिया थाना क्षेत्र के माचपल्ली, आरामझोरा और हिड्डूर के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। जैसे ही जवान जंगल के अंदर पहुंचे, नक्सलियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी।

इसके जवाब में सुरक्षाबलों ने भी मोर्चा संभाला और दोनों तरफ से तेज गोलीबारी हुई। मुठभेड़ के बाद हालात शांत होने पर इलाके की तलाशी ली गई, जिसमें एक महिला नक्सली का शव बरामद हुआ।

मुठभेड़ में मारी गई महिला नक्सली की पहचान रूपी के रूप में हुई है, जो एसीएम (एरिया कमेटी मेंबर) रैंक की कमांडर थी। लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की वांटेड सूची में शामिल रूपी बस्तर क्षेत्र में सक्रिय आखिरी तेलुगू महिला नक्सली कैडर मानी जा रही थी। वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद महिला नक्सली के अंतिम संस्कार के लिए तेलंगाना के मेडक जिले ले जाया गया, जहां अंतिम संस्कार के दौरान का वीडियो अब सामने आया है, जिसमें कुछ लोग लाल झंडे लेकर नाचते और विवादित गीत बजाते दिखाई दे रहे हैं। यह उसी तरह का मंजर था, जब हिडमा को अंतिम विदाई दी गई थी।

बस्तर में योजनाओं के सेचुरेशन पर फोकस तेज

मुख्य सचिव ने कहा- योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दें

जगदलपुर। मुख्य सचिव विकास शील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बस्तर संभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। बैठक में मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि, शासन की प्राथमिकता वाली सभी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने नियद नेल्लानार 2.0 और बस्तर मुन्ने अभियान के तहत मैदानी स्तर पर विशेष प्रयास करने कहा। उन्होंने कहा कि दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाए। इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें योजनाओं से जोड़ें। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि, एक स्पष्ट कार्ययोजना तैयार की जाए, जिसमें समय-सीमा तय कर लक्ष्य आधारित कार्य किया जाए। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित

मॉनिटरिंग और प्रगति की समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाए।

बस्तर मुन्ने अभियान के तहत आयोजित शिविरों को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएं, ताकि ग्रामीणों को अधिक सुविधा मिल सके और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो। इस बैठक में 1 मई से 10 जून तक आयोजित होने वाले सुशासन तिहार के लिए भी विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने कहा।

धमधा में महिला पर सूदखोरी

दुर्ग-भिलाई। दुर्ग जिले के धमधा क्षेत्र में सूदखोरी और चेक के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। पुलिस ने गंडई निवासी शोभा केशकर उर्फ निशा (47) के खिलाफ केस दर्ज किया है। उन पर मुसलमान पारा निवासी शहनाज बेगम (44) ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शहनाज बेगम ने नवंबर 2023 में शोभा केशकर से 20 हजार रुपए उधार लिए थे। यह लेन-देन 10 प्रतिशत मासिक ब्याज दर पर हुआ था। सुरक्षा के तौर पर शहनाज ने बैंक ऑफ बड़ौदा का एक कोरा चेक भी आरोपी को सौंपा था। पीड़िता के अनुसार, उन्होंने करीब 9 महीने तक हर माह 2000 रुपए ब्याज के रूप में चुकाए। इस तरह मूल रकम से कहीं अधिक राशि चुकाने के बावजूद उनका कर्ज खत्म नहीं हुआ। आर्थिक तंगी के कारण जब शहनाज कुछ महीनों तक ब्याज नहीं दे पाईं, तो आरोपी ने उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जनवरी 2025 में शहनाज के भाई सादिक रजा ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने 25 हजार रुपए में पूरा लेन-देन खत्म करने की बात तय करवाई। पीड़िता ने कुल मिलाकर लगभग 43 हजार रुपए चुका दिए। इसके बावजूद आरोपी ने न तो चेक लौटाया और न ही लेन-देन समाप्त माना। शहनाज बेगम का आरोप है कि शोभा केशकर ने उनके दिए कोरे चेक का दुरुपयोग करते हुए उसमें 1 लाख रुपए की राशि भर दी। चेक बाउंस होने के बाद कोर्ट के जरिए उन्हें नोटिस भेजा गया, जिससे उन पर मानसिक और आर्थिक दबाव बढ़ गया।

ग्राम पंचायत बेंद्री में पटेल नियुक्ति मामला पलटा

■ पूर्व आदेश को निरस्त कर फिर से पूरी प्रक्रिया को संपादित करने का दिया निर्देश

अभनपुर। ग्राम पंचायत बेंद्री में पटेल पद की नियुक्ति को लेकर उपजे विवाद पर न्यायालय अपर कलेक्टर, रायपुर ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए अपीलार्थी के पक्ष में फैसला सुनाया है।

न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित पूर्व के आदेश को निरस्त करते हुए अपील को स्वीकार कर लिया है। बेंद्री ग्राम पंचायत में पटेल की नियुक्ति में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन ना करने और आवेदक को अनुचित लाभ पहुंचाने का ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत की थी। लेकिन अनुविभागीय अधिकारी ने 18 नवंबर को लक्ष्मीनाथ साहू की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया था। इस आदेश को अपीलार्थी देव कुमार साहू ने चुनौती दी थी। न्यायालय द्वारा अभिलेखों एवं प्रस्तुत तर्कों का गहन परीक्षण करने पर पाया कि पटेल नियुक्ति के लिए एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों की स्थिति में आवश्यक मतदान प्रक्रिया संपन्न नहीं की गई। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर सीधे नियुक्ति की गई, जो विधि के विरुद्ध है। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जब एक से अधिक पात्र उम्मीदवार हों, तब संबंधित भू-स्वामियों की इच्छा के अनुसार मतदान या अन्य वैधानिक प्रक्रिया अपनाना आवश्यक है। केवल ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर नियुक्ति करना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर पटेल नियुक्ति की संपूर्ण प्रक्रिया विधि अनुसार पुनः संपादित करने के लिए निर्देशित किया।

बालको में अलाइसा एआई रोबोट तैनात

■ कर्मचारियों को रियल-टाइम सुरक्षा ट्रेनिंग, दक्षता में सुधार

कोरबा। कोरबा जिले में वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने अपने संयंत्र स्मेल्टर कॉम्प्लेक्स में 'अलाइसा' नाम की अत्याधुनिक एआई-संचालित ह्यूमनॉइड असिस्टेंट को तैनात किया है। यह शॉप फ्लोर पर काम करने वाले कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने, जानकारी देने और सही फैसले लेने में मदद करती है। औद्योगिक सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सिस्टम कर्मचारियों को काम के नियम, मशीनों की देखभाल और

जरूरी सुरक्षा नियमों की जानकारी तुरंत देता है। इससे कर्मचारी काम को बेहतर और सुरक्षित तरीके से कर पा रहे हैं। बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक राजेश कुमार ने कहा कि कंपनी तकनीक और कर्मचारियों की क्षमता दोनों के संतुलन पर विशेष ध्यान देती है। उन्होंने बताया कि 'अलाइसा' कंपनी के डिजिटल बदलाव की दिशा में बड़ा कदम है। इससे कर्मचारियों को सीखने और काम समझने में मदद मिल रही है। शुरुआत में 'अलाइसा' ने 100 से ज्यादा कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी है।यह लर्निंग मॉड्यूल, रियल-टाइम प्रश्न समाधान और मूल्यांकन-आधारित सिस्टम प्रदान करता है, जिससे सुपरवाइजर कर्मचारियों की समझ और कौशल प्रगति की प्रभावी निगरानी कर पा रहे हैं। इससे सुपरवाइजर भी कर्मचारियों की प्रगति देख पा रहे हैं। यह सिस्टम प्रक्रियाओं के मानकीकरण, सुरक्षा नियमों के अनुपालन को सुदृढ़ करने और उच्च-तीव्रता वाले औद्योगिक वातावरण में कार्यबल की तैयारी को बेहतर बना रहा है। इससे काम से जुड़ी समस्याओं का जल्दी समाधान हो रहा है और कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। प्रशिक्षु उदय चौहान ने बताया कि उन्होंने पॉटलाइन पर काम शुरू करने से पहले 'अलाइसा' से सुरक्षा ट्रेनिंग ली, जो किसी इंसान ट्रेनर जितनी ही अच्छी थी।

गवाहों को प्रभावित करने के आरोप, कंपनी ने कराया था कमरा बुक

बालको चिमनी हादसा होटल के कमरे से गवाह-आरोपी पकड़े गए

कोरबा। कोरबा में बालको चिमनी हादसे के मामले में एक महत्वपूर्ण गवाह को प्रभावित करने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी सगामसेट्टी व्येंकतेश के साथ गवाह पृथ्वीनाथ सिंह को होटल ग्रैंड गोविंदा के कमरा नंबर 202 से पकड़ा। यह कमरा जीडीसीएल कंपनी ने बुक कराया था। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और बिलासपुर हाईकोर्ट ने इसकी सुनवाई समय-सीमा में पूरी करने का आदेश दिया है। बता दें कि 2009 में बालको प्लांट में निर्माणाधीन चिमनी ढहने से 40 मजदूरों की मौत हो गई थी और कई घायल

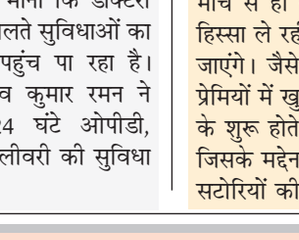

हुए थे। इस मामले में जीडीसीएल कंपनी और सेपको चीनी कंपनी के लोग आरोपी हैं। लंबे समय से जीडीसीएल कंपनी पर गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लग रहा था, जिसके कारण गवाह पेशी में नहीं आ रहे थे। न्यायालय ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। एसपी सिद्धार्थ तिवारी को सूचना मिली थी कि गवाह पृथ्वीनाथ सिंह आरोपी पक्ष कोरबा लाकर छिपाकर रखे हुए है, जो कि बिहार के छपरा का रहने वाला है। सूचना पर पुलिस टीम ने होटलों में छापेमारी शुरू की। पुलिस ने होटल ग्रैंड गोविंदा के कमरा नंबर 202 में गवाह पृथ्वीनाथ सिंह को उनके बेटे और एनएसजीएल कंपनी के पूर्व कर्मचारी और आरोपी सगामसेट्टी व्येंकतेश के साथ पाया। जांच में होटल के रजिस्टर से पता चला कि यह कमरा जीडीसीएल कंपनी की ओर से बुक किया गया था। पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी व्येंकतेश घबरा गया और उसका व्यवहार संदिग्ध लगा।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

आबकारी विभाग से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार

सूरजपुर। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई में फरार आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। नशीली दवाओं की बिक्री के मामले में पकड़ा गया आरोपी गिरफ्तारी के बाद सूरजपुर पुलिस को चकमा देकर फरार था, जिसे अब फिर से पकड़कर जेल भेजा है। आबकारी विभाग की संभागीय उड़नदस्ता टीम ने विश्रामपुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए आरोपी भोला को लगभग 300 नशीली टेबलेट के साथ उसके घर से गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के बाद आरोपी को सूरजपुर के आबकारी नियंत्रण कक्ष में दो आरक्षकों की निगरानी में रखा गया। इसी दौरान उसने पानी पीने का बहाना बनाकर दोनों आरक्षकों को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी के फरार होने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई, जो बाद में सामने आई। घटना के बाद आरोपी की तलाश तेज कर दी गई। आखिरकार पुलिस ने बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के आईटीआई कॉलोनी से आरोपी भोला को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 (सी) के तहत कार्रवाई की गई है।

ऑनलाइन नक्शा नहीं तो रजिस्ट्री नहीं, जिला प्रशासन सख्त

धमतरी। जिले में जमीन खरीदी-बिक्री को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। तहसीलदार के नए निर्देश जारी किए जाने के बाद प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा गया है। तहसीलदार ने बताया कि राजस्व प्रकरणों में नक्शा और सीमांकन से जुड़े बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें विवादित नक्शा और बटांकन के मामले शामिल हैं। तहसीलदार ने बताया कि कई मामलों में यह पाया है कि जहां ऑनलाइन नक्शा होना चाहिए, वहां बटर पेपर पर नक्शा बनाकर उप पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्री की जा रही है, जिससे विवाद बढ़ रहे हैं। इसी स्थिति को देखते हुए तहसीलदार ने उप पंजीयक और सभी पटवारियों स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन जमीनों का ऑनलाइन नक्शा उपलब्ध नहीं है, उनका पहले ऑनलाइन नक्शा कटवाना अनिवार्य होगा। बटर पेपर पर बनाए गए नक्शों के आधार पर किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। तहसीलदार कुसुम प्रधान ने ताजा मामले का उदाहरण देते हुए बताया कि एक सप्ताह पहले एक प्रकरण सामने आया था।

दुर्ग के किसानों ने किया पीडब्ल्यूडी का घेराव

दुर्ग। बोरीगारका-कातरो मार्ग के निर्माण में लोक निर्माण विभाग पर लापरवाही और तकनीकी त्रुटियों का आरोप लगाते हुए किसानों ने पीडब्ल्यूडी का घेराव किया। किसानों का आरोप है कि बार-बार चेतावनी देने के बाद भी पुल निर्माण नहीं किया गया। इससे किसानों की खेती पर संकट आ गया है। वहां कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पीडब्ल्यूडी पर 6 करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले का आरोप लगाया है। बोरीगारका के सरपंच का आरोप है कि सड़क निर्माण के दौरान नियमों को ताक पर रखकर सिंचाई निकासी नाले की अनदेखी की गई है, जहां नियमानुसार पुल का निर्माण अनिवार्य था वहां विभाग ने अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए सिर्फ पाइप डालकर खानापूर्ति कर दी है। किसानों ने इसे तकनीकी रूप से गलत बताते हुए एक हजार एकड़ कृषि भूमि सिंचाई बाधित होने का आरोप लगाया। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता एके आशीष भट्टाचार्य ने किसानों के प्रदर्शन और विभाग पर लगे आरोपों पर जवाब दिया।

जनकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 100 बेड का दावा

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। जिला मुख्यालय से लगभग 110 किलोमीटर दूर वनांचल क्षेत्र में जनकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित है। जहां दूर दूर से लोग इलाज कराने आते हैं। अस्पताल में सिर्फ 3 डॉक्टर है, जिन पर 83 पंचायतों के लोगों के इलाज के जिम्मेदारी है। मरीजों के बढ़ते दबाव के बीच साल 2024 में इसे 100 बेड अस्पताल बनाने की घोषणा की गई। लेकिन अब भी अस्पताल में सिर्फ 74 बेड ही संचालित है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार कम सुविधा में मरीजों को बेहतर इलाज देने की कोशिश की जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 24 घंटे ओपीडी, ऑपरेशन, डिलीवरी और एनआरसी (पोषण पुनर्वास केंद्र) जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने माना कि डॉक्टरों और स्टाफ की भारी कमी के चलते सुविधाओं का पूरा लाभ मरीजों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जनकपुर बीएमओ डॉ। राजीव कुमार रमन ने बताया कि अस्पताल में 24 घंटे ओपीडी, केजुअलटी, ऑपरेशन और डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है।

आईपीएल मैच में सट्टा, दांव लगाते कोरबा पुलिस ने पकड़ा

कोरबा। खेल प्रेमियों में आईपीएल का खुमार चढ़ा हुआ है। इधर क्रि केट को लेकर सटोरिए भी सक्रिय हैं। हर दिन मैच होने के कारण सटोरियों के लिए भी यह किसी त्योहार से काम नहीं है। जो हार व जीत को लेकर ऑन लाइन सट्टे पर दांव लगा रहे हैं। इसका खुलासा उस वक्त हुआ, जब पुलिस व साइबर सेल की संयुक्त टीम ने एक सटोरिए को अपने कब्जे में लिया। वह अपने साथी के साथ मिलकर खेलो बाजी बुक नामक प्लेटफार्म के माध्यम से दांव लगवा रहा था। उसके मोबाइल में भारी रकम लेनदेन के हिसाब किताब और 72 हजार रुपए बैलेंस मिले हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानि आईपीएल के 19 वें संस्करण की शुरूआत 28 मार्च से हो गई है। इस प्रतियोगिता में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उनके बीच कुल 74 मैच खेले जाएंगे। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है, खेल प्रेमियों में खुमार भी बढ़ता जा रहा है। आईपीएल के शुरू होते ही सटोरिए भी सक्रिय हो गए हैं। जिसके मद्देनजर पुलिस कप्तान सिद्धार्थ तिवारी ने सटोरियों की निगरानी बढ़ा दी है।

बिलासपुर में डुप्लीकेट गोल्ड फ्लैक सिगरेट पकड़ाया

■ दिल्ली आईटीसी टीम ने ग्राहक बनकर पकड़ा 5 लाख का माल, व्यापार विहार में हो रही थी सप्लाई

बिलासपुर। बिलासपुर में डुप्लीकेट गोल्ड फ्लैक कंपनी की सिगरेट का भंडाफोड़ हुआ है। व्यापार विहार स्थित मालधक्का में नकली सिगरेट की सप्लाई हो रही थी। दिल्ली आईटीसी की टीम ने ग्राहक बनकर नकली सिगरेट की बड़ी खेप पकड़ी है। व्यापार विहार इलाके में एक व्यापारी के पास से करीब 5 लाख रुपए की 4 कार्टून सिगरेट बरामद किया गया है। यह कारोबारी शहर में छोटे-बड़े दुकानदारों को थोक में सिगरेट सप्लाई कर रहा था। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। दरअसल, दिल्ली की आईटीसी को पहले ही

सूचना मिली थी कि, शहर में नकली सिगरेट की सप्लाई हो रही है। जिस पर बुधवार को टीम के सदस्य बिलासपुर पहुंचे। पहले उन्होंने पान-ठेलों से सैंपल लिए और सिगरेट की जांच की। जिसमें दुकानों में बिक रहे सिगरेट नकली पाए गए। टीम के सदस्यों ने दुकानदारों से सिगरेट की सप्लाई की जानकारी ली।

जिसके बाद टीम के सदस्यों ने ग्राहक बनकर सिगरेट की डिमांड की। इस दौरान कारोबारी ने उन्हें महाराणा प्रताप चौक स्थित निगम कॉलोनी के पास बुलाया। जहां थोक सप्लायर रोशन चंदानी की फर्म में आने की जानकारी दी। इस पर टीम के सदस्य सीधे रोशन चंदानी की दुकान पहुंच गए। टीम के सदस्यों ने यहां सिगरेट की जांच की और ओरिजनल पैकेट और स्टिक से मिलान किया। जिसमें दुकान का माल नकली निकला। इसके बाद टीम के सदस्य सिविल लाइन थाने पहुंचे। जब्त माल को भी थाने ले जाया गया। यहां देर रात तक पुलिस की कार्रवाई चलती रही। टीआई एसआर साहू ने बताया कि इस मामले में कार्रवाई चल रही है, जांच के बाद केस दर्ज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि नकली सिगरेट का यह कारोबार रोजाना 2 लाख रुपए से ज्यादा का है। वहीं, असली और नकली की पहचान पैक की प्रिंटिंग, होलोग्राम, कोड, स्टिक की बनावट और स्वाद से की जाती है। शहर के छोटी दुकानों में यहां से सिगरेट की सप्लाई की जाती है। शहर में नकली सिगरेट का खेप पकड़े जाने की जानकारी मिलते ही कारोबारी रोशन चंदानी के परिचित व्यापारी सिविल लाइन थाना पहुंचने लगे। देर रात तक यहां व्यापारियों की भीड़ जुटी रही। बताया जा रहा है कि कुछ व्यापारी उसे छोड़ने के लिए दबाव भी बना रहे थे।

ऐसे करें असली और नकली गोल्ड फ्लेक सिगरेट की पहचान

पैक की प्रिंटिंग और होलोग्राम
आईटीसी का लोगो और सुरक्षा कोड
सिगरेट स्टिक की बनावट
तंबाकू की क्वालिटी और महक
स्वाद बिल्कुल अलग और धुएं से जलन कम

बीजापुर में अतिक्रमण पर 74 लोगों को नोटिस

बीजापुर। बीजापुर जिले के भोपालपटनम नगर में लंबे समय से नेशनल हाईवे के किनारे जमे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन अब सख्त रवैया अपनाने में जुट गया है। जिला मुख्यालय के चट्टान पारा में हाल ही में हुए बुलडोजर एक्शन के बाद भोपालपटनम प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। नगर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था और भविष्य में प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार लक्ष्मण कुमार राठिया ने बुधवार को 74 मकान और दुकान मालिकों को नोटिस जारी कर पेशी पर तलब किया है। प्रशासन के इस कड़े रुख से नगरवासियों में चर्चा का माहौल है। व्यापारियों द्वारा सड़कों पर

शेड निकालना और मकान मालिकों द्वारा नालियों के ऊपर अवैध पक्का निर्माण करने से शहर की स्थिति खराब हो गई है। सूचना मिलते ही कई दुकानदारों ने जल्दबाजी में अपना सामान हटाना शुरू कर दिया। चर्चा है कि प्रशासन इस बार केवल औपचारिकता नहीं करेगा, बल्कि चट्टान पारा की तर्ज पर यहां भी अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। नोटिस पाने वाले 74 लोगों को तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण के कारण बाजार में आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। भोपालपटनम तहसीलदार लक्ष्मण कुमार राठिया ने बताया कि नगर में बढ़ते अतिक्रमण के कारण यातायात पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। आने वाले समय में नेशनल हाईवे और मुख्य मार्गों का चौड़ीकरण प्रस्तावित है, जिसके लिए शासकीय भूमि खाली कराना जरूरी है। फिलहाल 74 मकान और दुकान मालिकों को नोटिस जारी कर पेशी के लिए बुलाया गया है। यदि तय समय में स्वेच्छा से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त करेगा।

संक्षिप्त समाचार

भीषण गर्मी को देखते हुए अब 20 अप्रैल से 15 जून तक रहेगा स्कूलों में अवकाश

रायपुर। प्रदेश में बढ़ती भीषण गर्मी और लू के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्कूलों के ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में आंशिक संशोधन किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि बढ़ती भीषण गर्मी में बच्चों की सेहत की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित करना हम सब की जिम्मेदारी है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूर्व निर्धारित ग्रीष्मकालीन अवकाश को पहले लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि इस भीषण गर्मी में बच्चों की सेहत सुरक्षित रह सके। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पूर्व में दिनांक 01 मई 2026 से 15 जून 2026 तक घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश में संशोधन करते हुए अब दिनांक 20 अप्रैल 2026 से 15 जून 2026 तक अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश प्रदेश के समस्त शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त एवं अशासकीय शालाओं पर लागू होगा।

अब दिखा भीषण गर्मी का असर

रायपुर। भीषण गर्मी का प्रकोप अब असर दिखाने लगा है। सुबह 11 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में गर्मी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश के मध्य हिस्सों में खासकर 16 से 19 अप्रैल के बीच बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग में लू (हीट वेव) का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ा है और अगले 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री और बढने के आसार हैं। बता रहे हैं राजनांदगांव में तापमान 43 डिग्री पहुंच गया है,जबकि अभी अप्रैल मध्य का महीना है,मई अभी बाकी है।

नगरीय प्रशासन विभाग ने 9 बी.टी. सड़कों के लिए डेढ़ करोड़ मंजूर किए

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर नगर पंचायत में 9 बी.टी. सड़कों के लिए एक करोड़ 49 लाख 55 हजार रुपए मंजूर किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इनकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री श्री अरुण साव ने सभी कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में काम पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विकास ने भानुप्रतापपुर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-7 में दो बी.टी. सड़कों के लिए 47 लाख 54 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। विभाग द्वारा वार्ड क्रमांक-1 में बी.टी. रोड के लिए 21 लाख 82 हजार रुपए, वार्ड क्रमांक-2 के लिए 5 लाख 95 हजार रुपए तथा वार्ड क्रमांक-9 के लिए 6 लाख एक हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने वार्ड क्रमांक-10 में दुर्गा मंदिर से मंडी तक बी.टी. रोड के लिए 23 लाख 81 हजार रुपए, वार्ड क्रमांक-12 में बी.टी. रोड के लिए 16 लाख 9 हजार रुपए, वार्ड क्रमांक-13 के लिए 21 लाख 39 हजार रुपए एवं वार्ड क्रमांक-14 में 6 लाख 94 हजार रुपए बी.टी. सड़क के लिए स्वीकृत किए हैं।

टिंबर मार्केट में लगी आग, प्लाईवुड सहित लाखों का सामान जलकर खाक

रायपुर। फाफाडीह स्थित टिंबर मार्केट के पायनियर मार्केटिंग के कैलाश टिंबर गोदाम में बुधवार देर रात भीषण आग लगने से गोदाम में रखे लकड़ी और लेमिनेटेड प्लाईवुड सहित लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल पुलिस मामले मामले की जांच में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 6 से अधिक गाडियां मौके पर पहुंचीं। उसके बाद तड़के तक गाडियां आती जाती रहीं। गुरुवार दोपहर तक आग बुझाने का काम जारी रहा। इसमें डेढ़ दर्जन गाडियां इस्तेमाल की गई। निगम के टैंकरों से भी पानी मंगवाया गया। आग से गोदाम में रखा प्लाईवुड सहित लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

उधना-सांतरागाछी के बीच तीन-तीन फेरो के लिए आज से चलेगी स्पेशल ट्रेन

रायपुर/बिलासपुर। रेलवे ने उधना-सांतरागाछी-उधना के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष ट्रेन 3-3 फेरे लगाएगी, जिससे यात्रियों को कंफर्म बर्थ और आरामदायक यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। रेलवे के अनुसार, गाड़ी संख्या 09073 उधना-सांतरागाछी स्पेशल ट्रेन 17, 22 और 24 अप्रैल को उधना से रवाना होगी। वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 09074 सांतरागाछी-उधना स्पेशल ट्रेन 19, 24 और 26 अप्रैल 2026 को सांतरागाछी से चलेगी। इस स्पेशल ट्रेन का ठहराव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के प्रमुख स्टेशनों गोंदिया, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में दिया गया है। उधना से चलने वाली ट्रेन सुबह 11.25 बजे रवाना होकर अगले दिन तड़के गोंदिया (02.30 बजे), दुर्ग (05.03 बजे), रायपुर (05.43 बजे) और बिलासपुर (07.30 बजे) पहुंचेगी। इसके बाद यह ट्रेन रात 9.00 बजे सांतरागाछी पहुंचेगी। वहीं, वापसी में सांतरागाछी से ट्रेन रात 12.05 बजे रवाना होकर दोपहर 12.00 बजे बिलासपुर पहुंचेगी। इसके बाद रायपुर, दुर्ग और गोंदिया होते हुए अगले दिन सुबह 10.00 बजे उधना पहुंचेगी। इस स्पेशल ट्रेन में कुल 22 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें 2 लगेज-सह-दिव्यांग कोच, 1 पेंट्रीकार, 11 सामान्य कोच और 8 स्लीपर कोच शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ में जनगणना अभियान का आगाज, सीएम साय ने की स्व-गणना

कहा - देश और राज्य के भविष्य की दिशा तय करने का आधार है जनगणना, नागरिकों से सक्रिय भागीदारी की अपील

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में जनगणना 2027 के तहत ऑनलाइन स्व-गणना कर जनगणना अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर नागरिकों को इस राष्ट्रीय कार्य में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा जनगणना अभियान संचालित हो रहा है और छत्तीसगढ़ में भी आज से ऑनलाइन स्व-गणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि नागरिक 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के बीच ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार से संबंधित जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार जनगणना को आधुनिक और डिजिटल स्वरूप दिया गया है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुलभ हो सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि देश और राज्य के भविष्य की दिशा तय करने का आधार है। इन आंकड़ों के आधार पर सरकार आने वाले वर्षों की योजनाएं तैयार करती है, ताकि विकास का लाभ हर वर्ग तक प्रभावी रूप से पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 मई 2026 से जनगणना का पहला चरण शुरू होगा, जिसमें मकान सूचीकरण और गणना का कार्य किया जाएगा। 30 मई तक प्रगणक घर-घर जाकर आवासीय और गैर-आवासीय भवनों, उनकी स्थिति, उपयोग तथा बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, बिजली, रसोई गैस, इंटरनेट और संचार व्यवस्था से संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे।

उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह करते हुए कहा कि जब भी प्रगणक घर आएं, तो उन्हें सही, स्पष्ट और पूर्ण जानकारी दें, क्योंकि प्रत्येक जानकारी राज्य के विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि जनगणना के दौरान दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाती है और इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय एवं नीतिगत उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है और विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के संकल्प को साकार करने में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है। सही आंकड़े ही बेहतर योजना और प्रभावी विकास की नींव रखते हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से इस महाअभियान को जनभागीदारी का उत्सव बनाने और सक्रिय सहयोग देने की अपील की।

इस दौरान अपर मुख्य सचिव तथा जनगणना के नोडल श्री मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर रायपुर डॉ. गौरव कुमार सिंह, संचालक जनगणना श्री कार्तिकेय गोयल सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

मुख्य सचिव विकासशील ने भी स्व-गणना के तहत अपनी जानकारी दर्ज की

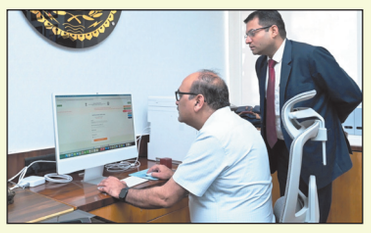

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के तारतम्य में 16 से 30 अप्रैल 2026 तक स्व-गणना की प्रक्रिया की शुरूआत हुई है। गुरुवार को यहां मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव श्री विकासशील ने स्व-गणना के तहत स्वयं अपनी जानकारी दर्ज की। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज कुमार पिंगुआ, छत्तीसगढ़ जनगणना निदेशक श्री कार्तिकेय गोयल सहित जनगणना निदेशालय के अधिकारी भी मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि इस सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें और अपनी जानकारी स्वयं भरकर जनगणना में सक्रिय भागीदारी निभाएं। राज्य में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक नागरिकों को स्व-गणना के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज करने का अवसर दिया गया है। आज अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज कुमार पिंगुआ ने भी स्व-जनगणना के तहत अपनी जानकारी पोर्टल पर जानकारी दर्ज की। स्व-गणना के लिए https://se.census.gov.in/ पोर्टल पर जाकर आसानी से विवरण भरा जा सकता है। मुख्य सचिव ने कहा है कि यह पहल जनगणना प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और अधिक विश्वनीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे लोग अपनी सही और पूरी जानकारी स्वयं साझा कर सकेंगे। स्व-गणना अवधि समाप्त होने के बाद, 1 मई से 30 मई तक जनगणना टीम घर-घर जाकर लोगों से जानकारी एकत्रित करेगी। प्रगणक घर-घर आकर जानकारी दर्ज करेंगे। हर मकान की जानकारी दर्ज की जाएगी। घर की स्थिति, सुविधाएं और मूलभूत जानकारी संकलित की जाएगी। जिन्होंने स्व-गणना के तहत जानकारी दर्ज की है वे जनगणना प्रगणकों के घर आने पर उनसे स्थ्व द्धष्ठ जरूर साझा करें। यदि कोई स्व-गणना नहीं कर पाते है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में 1 मई से 30 मई 2026 तक की अवधि में प्रगणक आपके घर आकर जानकारी अवश्य दर्ज करेंगे। सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस अवसर पर जनगणना निदेशालय के संयुक्त संचालक श्री प्रदीप साव सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए।

भाजपा का सवाल : आधी आबादी को उसका अधिकार देने से कांग्रेस को दिक्कत क्यों?

■ नारी शक्ति वंदन अधिनयम का विरोध कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता डॉ. (श्रीमती) किरण बघेल ने नारी शक्ति वन्दन अधिनयम के विषय में कांग्रेस की टिप्पणी का पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा नारी शक्ति वन्दन पर दिया गया बयान हास्यास्पद है। कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि भाजपा श्रेय की राजनीति कर रही है, जबकि भाजपा नारी शक्ति वन्दन अधिनयम के माध्यम से मातृ शक्ति को उनका अधिकार देने का कार्य किसी प्रकार का श्रेय लेने के लिए नहीं अपितु महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए कर रही है ।

श्रीमती बघेल ने कहा कि देश की आधी आबादी को निश्चित ही यह अधिकार मिलना चाहिए। जिसे दशकों तक सत्ता में स्थापित रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। जिस अधिनियम को दशकों पहले पारित हो जाना चाहिए था, वह लंबित रहा और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ उठने लगा। श्रीमती बघेल ने कहा कि महिला होने के नाते मैं एक बात कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहना चाहती हूं कि महिलाओं को दशकों तक उनके अधिकार से वंचित रखने के बाद भी यदि कांग्रेसी नेता नारी शक्ति वन्दन अधिनयम के विषय में राजनीतिक टिप्पणी एवं विरोध कर रहे हैं, तो यह कांग्रेस की नाकामी का प्रमाण बनने के साथ साथ जगहँसाई का माध्यम भी बनेगा।

देश की महिलाओं में नारी शक्ति वन्दन अधिनयम को लेकर उत्साह का माहौल है। महिलाओं ने नारी शक्ति वन्दन अधिनयम के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार माना है।

लक्ष्मी वर्मा ने ली राज्यसभा सदस्य की शपथ

नई दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने गुरुवार को देश के गौरवशाली उच्च सदन (राज्यसभा) में सदस्यता की आधिकारिक शपथ ग्रहण की। इस ऐतिहासिक अवसर पर उन्होंने न केवल प्रदेश की तीन करोड़ जनता के अधिकारों की आवाज को सदन में बुलंद करने का संकल्प लिया, बल्कि अपने परिधान के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अस्मिता को भी राष्ट्रीय पटल पर गरिमामय ढंग से प्रस्तुत किया।

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सांसद लक्ष्मी वर्मा ने एक विशेष रूप से डिज़ाइन की गई साड़ी धारण की थी, जिसने संसद भवन में सभी का ध्यान आकर्षित किया। यह परिधान पूर्णतः छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और धरोहर का प्रतिनिधित्व कर रहा था। साड़ी के मुख्य भाग पर प्रदेश के ऐतिहासिक और पुरातात्विक गौरव 'भोरमदेव मंदिर' की सुंदर आकृति और प्रदेशवासियों की अगाध आस्था की प्रतीक 'छत्तीसगढ़ महतारी' का भव्य चित्र उकेरा गया था। इसके अतिरिक्त साड़ी की किनारी (बॉर्डर/लेयर) पर पारंपरिक छत्तीसगढ़ी अभिवादन 'जय जोहार' स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ था, जो प्रदेश की सादगी, आत्मीयता और भाईचारे का सशक्त संदेश दे रहा था।

अपने इस विशेष परिधान से मातृभूमि को नमन करते हुए लक्ष्मी वर्मा ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि वे उच्च सदन में केवल एक जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की माटी और संस्कृति की सच्ची संवाहक के रूप में उपस्थित हुई हैं। इस गौरवपूर्ण अवसर पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए सांसद लक्ष्मी वर्मा ने कहा, गुरुवार को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेना मेरे सार्वजनिक जीवन का अत्यंत भावुक और सर्वोच्च क्षण है। आज मैंने जो परिधान धारण किया है, वह मेरे लिए मात्र एक वस्त्र नहीं है, बल्कि यह मेरे प्रदेश की पहचान, हमारी गौरवशाली परंपरा और 'छत्तीसगढ़ महतारी' का साक्षात आशीर्वाद है। मैं शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं।

उन्होंने कहा, उच्च सदन में मेरा हर कदम और मेरी हर आवाज प्रदेश के सर्वांगीण विकास और हमारी सांस्कृतिक अस्मिता के संरक्षण के लिए पूर्णतः समर्पित होगी। लक्ष्मी वर्मा द्वारा उच्च सदन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति के इस अनूठे और गौरवशाली प्रदर्शन की प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सराहना हो रही है। इस पहल ने छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित किया है।

आरटीई भुगतान को लेकर निजी स्कूलों का आंदोलन तेज

■ आज प्रतीकात्मक विरोध 18 को स्कूल बंद

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है। एसोसिएशन के आह्वान पर 17 अप्रैल को प्रदेशभर के निजी स्कूलों में शिक्षक और संचालक काली पट्टी बांधकर काम करेंगे, वहीं 18 अप्रैल को सभी निजी स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे।

एसोसिएशन के अनुसार 17 अप्रैल को स्कूल खुले रहेंगे और पढ़ाई भी जारी रहेगी, लेकिन शिक्षक और संचालक काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे। यह प्रदर्शन प्रतीकात्मक होगा, ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो और संदेश भी पहुंचे।

18 अप्रैल को प्रदेश के सभी निजी स्कूल बंद रखे जाएंगे। इस दिन कक्षाएं नहीं लगेंगी और विद्यार्थियों की छुट्टी रहेगी। एसोसिएशन का कहना है कि सरकार तक अपनी मांगों को मजबूती से पहुंचाने के लिए यह कदम जरूरी है।

निजी स्कूल संचालकों की मुख्य मांग आरटीई के तहत मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने और लंबित भुगतान को जल्द जारी करने की है। उनका कहना है कि लंबे समय से भुगतान नहीं होने और राशि कम होने के कारण स्कूलों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि प्रतिपूर्ति राशि के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित है, जिससे स्कूलों की स्थिति प्रभावित हो रही है।

एसोसिएशन ने सरकार से यह भी मांग की है कि शासकीय स्कूलों में प्रति छात्र होने वाले खर्च को सार्वजनिक किया जाए, ताकि उसी आधार पर निजी स्कूलों के लिए उचित प्रतिपूर्ति तय हो सके।

निजी स्कूल प्रबंधन 1 मार्च से असहयोग आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में 4 अप्रैल को निर्णय लिया गया था कि आरटीई के तहत वंचित वर्ग के छात्रों को नए प्रवेश नहीं दिए जाएंगे।

14 अप्रैल को हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में यह तय किया गया कि जब तक प्रतिपूर्ति राशि नहीं बढ़ाई जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। एसोसिएशन ने साफ कहा है कि मांगें पूरी नहीं होने पर आगे और कड़े कदम उठाए जाएंगे।

सहायक शिक्षक के 2292 पदों पर की जाएगी भर्ती

■ परीक्षा 11 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित

रायपुर। मुख्यमंत्री, श्री विष्णु देव साय द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कुल 5000 शिक्षकीय पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इसी क्रम में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सहायक शिक्षक के 2292 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया जा रहा है। इन पदों में से 795 पद ई-संवर्ग की शालाओं तथा 1497 पद टी-संवर्ग की शालाओं में भरे जाएंगे। उक्त पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, आयु सीमा एवं अन्य शर्तें विस्तृत विज्ञापन में उल्लिखित रहेंगी।

लोक शिक्षण संचालनालय के उपसंचालक श्री अशोक नारायण बंजारा ने बताया कि विस्तृत विज्ञापन छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट https://vyapamcg.cgstate.gov.in/ एवं स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट https:// eduportal.cg.nic.in/ पर जारी किया जाएगा तथा भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम भी व्यापम की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इन पदों हेतु लिखित भर्ती परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा किया जाएगा, जिसकी संभावित तिथि 11 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि संबंधी जानकारी व्यापम द्वारा पृथक से जारी की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप व्याख्याता एवं शिक्षक के पदों पर भर्ती हेतु पृथक से विज्ञापन भी जारी किए जाएंगे।

अक्षय तृतीया पर छत्तीसगढ़ में गठित होगा मंदिर महासंघ

जून माह में राज्य में एक भव्य मंदिर न्यास परिषद का होगा आयोजन

रायपुर। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ में मंदिर महासंघ का गठन किया जाएगा। यह बात गठित होने वाले मंदिर महासंघ के राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट, छग संयोजक मदन मोहन उपाध्याय और हिन्दू जनजागृति समिति के समन्वयक हेमंत कानस्कर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि यह महासंघ मंदिरों में दर्शनार्थी श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू करेगा। साथ ही मंदिरों को सरकारीकरण से मुक्त कराने, मंदिरों की जमीन पर कब्जे के खिलाफ काम करेगा। महासंघ मंदिरों की सुरक्षा एवं पुजारियों का संगठन, मंदिरों की संपर्क यंत्रणा, आपसी समन्वय, मंदिरों की समस्याए, मंदिर सनातन धर्म प्रचार के केंद्र बने इस उद्देश्य से भी काम करेगा।

सुनील घनवट ने बताया कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में 80 से अधिक मंदिरों के न्यासियों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें निर्णय लिए गए। इसी कड़ी में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 19 अप्रैल को मंदिर महासंघ छत्तीसगढ़ की औपचारिक स्थापना की जाएगी और जून माह में राज्य में एक भव्य मंदिर न्यास परिषद का आयोजन किया जाएगा। घनवट ने कहा कि अब तक महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में 17,000 से अधिक मंदिर, न्यासी और पुजारी इस महासंघ से जुड़ चुके हैं। मंदिर महासंघ का मुख्य ध्येय सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों को मुक्त कर उन्हें भक्तों को सौंपना है। इसके साथ ही मंदिरों की पवित्रता बनाए रखने के लिए वहां वस्त्र संहिता (ड्रेस कोड) लागू करना और मंदिर संस्कृति पर होने वाले हर आघात का संवैधानिक मार्ग से उत्तर देना यह महासंघ की प्राथमिकता है। महासंघ ने सरकार से मांग की है कि मंदिरों और मठों की हड़पी गई भूमि को मुक्त कराने के लिए कठोर एन्टी लैंड ग्रैबिंग एक्ट लागू किया जाए और वक़्फ बोर्ड के अवैध कब्ज़े से मंदिरों की भूमि छुड़ाई जाए। साथ ही भक्तों द्वारा मंदिरों को दान में दी गई भूमि पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क (स्टैम्प ड्यूटी) को पूर्णतः समाप्त करने की भी मांग की जा रही है।

छत्तीसगढ़ की स्थानीय समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में मंदिरों और मठों की भूमि पर अवैध अतिक्रमण, उनकी अवैध बिक्री और हस्तांतरण जैसी गंभीर समस्याएं हैं। इसी संदर्भ में छत्तीसगढ़ में एन्टी लैंड ग्रॅबिंग ?क्ट बने तथा आपातकालीन स्थितियों में मंदिरों को अपेक्षित सहायता न मिलने जैसी बाधाओं को दूर करने के लिए मंदिर महासंघ सक्रिय रूप से कार्य करेगा। इसके लिए पूरे राज्य में मंदिर न्यासियों, पुरोहितों और पुजारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी ताकि मंदिर प्रबंधन और धार्मिक विधि शास्त्रोक्त पद्धति से संपन्न हों।

पत्रकार वार्ता में मंदिर महासंघ छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला संयोजक श्री. मदन मोहन उपाध्याय, सह-संयोजक श्री. प्रवेश तिवारी, हिंदू जनजागृति समिति के श्री. कमल बिस्वाल, श्री. हेमंत कानसकर, श्री. आशीष परेड़ा, श्री. रोहित तिरंगा तथा नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के पूज्य श्री. नीलकंठ त्रिपाठी महाराज उपस्थित थे।

डॉ. हरलीन कौर ने हासिल किया पीएचडी की उपाधि

रायपुर। कलिंगा विश्वविद्यालय,नया रायपुर के विधि संकाय की सहायक प्राध्यापक हरलीन कौर को कलिंगा विश्वविद्यालय के द्वारा पीएच.डी. उपाधि से सम्मानित किया गया। उनके शोधकार्य का विषय जेन्डर न्यूट्रेलिटी इन इंडियन लॉः ए क्रिटिकल एक्जामिनेशन आफ मेन्स राईटस एंड लीगल रिफार्म्स था। उन्होंने अपना शोध कार्य कलिंगा विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉ. विवेक मलिक के निर्देशन में पूर्ण किया। उनका शोध कार्य विधि और मानवाधिकार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला रहा है, जिसे विश्वविद्यालय एवं शोध विद्वानों के द्वारा सराहा गया है।

ज्ञातव्य है कि डॉ. हरलीन कौर, अवंती बिहार रायपुर निवासी श्री परमजीत सिंह एवं श्रीमती हरप्रीत कौर की सुपुत्री और सरदार करणजीत सिंह की बहन हैं। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा एवं पीएचडी उपाधि के लिए अपने दादा स्व. श्री हुकुम सिंह एवं दादी स्व. सरदानी सतवंत कौर तथा नाना स्व. सरदार कृपाल सिंह एवं नानी स्व. सरदार प्रकाश के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किया है। वर्तमान में डॉ. हरलीन कौर कलिंगा विश्वविद्यालय में विधि संकाय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्य कर रही हैं।

युद्ध के बाद अरब देशों का भरोसा अमेरिका से उठा

नीरज कुमार दुब

मध्य पूर्व आज बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन का ज्वलंत उदाहरण बन चुका है। जिस अमेरिका ने दशकों तक इस क्षेत्र को अपनी रणनीतिक मुट्ठी में रखा, वही आज यहां अपनी पकड़ खोता नजर आ रहा है। पहले गाजा में तबाही और अब ईरान युद्ध से उपजे हालात अरब देशों को गहरी चिंता में डाल गये हैं। गाजा में हमले और ईरान युद्ध से लाखों लोग बेघर हुए, हजारों जिंदगियां खत्म हुईं और पूरे क्षेत्र में तबाही का मंजर फैल गया। इस सबसे अरब दुनिया के लोगों के दिल और दिमाग में बड़ा बदलाव आया है। हम आपको बता दें कि अरब दुनिया में अब अमेरिका के लिए भरोसा लगभग खत्म हो चुका है। जनता उसे एक पक्षीय, अवसरवादी और नैतिक रूप से कमजोर शक्ति के रूप में देख रही है। इसके उलट चीन और रूस को अधिक संतुलित और भरोसेमंद विकल्प माना जाने लगा है। लोग अब यह मानने लगे हैं कि अमेरिका अंतरराष्ट्रीय कानून की बात केवल तब करता है जब उसे फायदा हो। अरब देश यह भी देख रहे हैं कि गाजा अब भी मलबे में दबा है और वहां पुनर्निर्माण की कोई ठोस पहल नजर नहीं आती। इसके अलावा, इस युद्ध की सबसे भारी कीमत खाड़ी देशों को चुकानी पड़ रही है। पर्यटन, जो उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वह बुरी तरह हिल गया है। अनुमान है कि पर्यटन राजस्व में 13 अरब से 32 अरब डॉलर तक की गिरावट आ सकती है। यह गिरावट तब हो रही है जब 2024 में इन देशों ने पर्यटन से 120 अरब डॉलर का राजस्व कमाया था। इतना ही नहीं, एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार अरब देशों को इस युद्ध से करीब 200 अरब डॉलर तक का कुल नुकसान हो सकता है। यानी यह सिर्फ आर्थिक झटका नहीं, बल्कि दीर्घकालिक संकट का संकेत है। इसके अलावा, खाड़ी देशों ने दशकों तक अमेरिका को अपने यहां सैन्य अड्डे बनाने की अनुमति देकर यह भरोसा किया था कि इससे उनकी सुरक्षा मजबूत होगी और वह किसी भी बाहरी खतरे से सुरक्षित रहेंगे। लेकिन ईरान के साथ हालिया युद्ध ने इस धारणा को गहरे स्तर पर झकझोर दिया है। हकीकत यह सामने आई कि यही अमेरिकी अड्डे खाड़ी देशों के लिए सबसे बड़ा जोखिम बन गए। ईरान ने सीधे तौर पर उन ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जहां अमेरिकी मौजूदगी थी और इसके चलते हमले खाड़ी देशों की जमीन पर हुए। नतीजा यह हुआ कि नुकसान केवल अमेरिका का नहीं, बल्कि खाड़ी देशों का भी हुआ और उनकी सुरक्षित निवेश गंतव्य तथा स्थिर क्षेत्र की छवि को गहरा आघात पहुंचा। इसलिए सबसे गंभीर सवाल यह उठता है कि जब संकट की घड़ी आई तो अमेरिका अपने ही सैन्य अड्डों के आसपास स्थित देशों को पूर्ण सुरक्षा नहीं दे सका। ऐसे में अब यह बहस तेज हो रही है कि क्या खाड़ी देश भविष्य में अमेरिका को अपने यहां सैन्य मौजूदगी जारी रखने देंगे या वह इस पर पुनर्विचार करेंगे। यह घटनाक्रम पूरी दुनिया को यह संदेश भी देता है कि किसी बाहरी शक्ति को अपने भूभाग पर सैन्य अड्डे देने की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। इसलिए मध्य पूर्व में आने वाले समय में रणनीतिक स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अरब देश समझ रहे हैं कि अमेरिका की अगुवाई वाली व्यवस्था अब दरक रही है। अरब देश अब खुलकर या चुपचाप अपने विकल्प तलाश रहे हैं। चीन और रूस के साथ रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। रक्षा सहयोग बढ़ रहा है, व्यापारिक साझेदारियां गहरी हो रही हैं और नए बहुपक्षीय मंचों की ओर झुकाव साफ दिख रहा है। साथ ही खाड़ी देशों ने युद्ध से पहले अमेरिका को चेताया था, लेकिन उनकी अनदेखी की गई। अब जब वह खुद नुकसान झेल रहे हैं, तो वह अपने निवेश और गठबंधनों पर दोबारा सोचने को मजबूर हैं।

बिहार में संभावनाएं विकास की, अब सत्ता सम्राट की

ललित गर्ग

बिहार की राजनीति लंबे समय से बदलाव, प्रयोग और नेतृत्व के उतार-चढ़ाव का साक्षी रही है। ऐसे परिदृश्य में जब लंबे इंतजार और जटिल कूटनीतिक समीकरणों के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शासन स्थापित होने की स्थिति बनती है और सम्राट चौधरी जैसे नेता मुख्यमंत्री के रूप में उभरते हैं, तो यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि एक संभावित राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तन का संकेत भी है। यह क्षण बिहार के लिए एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, जहां अपेक्षाएं केवल शासन परिवर्तन की नहीं, बल्कि शासन की गुणवत्ता, दृष्टि और परिणामों की भी हैं। नये मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी के सामने न सिर्फ बिहार की जनता में एक कुशल प्रशासक की छाप छोड़ने की चुनौती है, बल्कि पार्टी की अपेक्षाओं एवं नीतीश कुमार द्वारा खींची रेखाओं से आगे निकलने के संघर्ष में भी उन्हें खरा उतरना होगा। सम्राट को उससे आगे ऐसा कुछ करना होगा, ताकि भाजपा उसके आधार पर भविष्य की दावेदारी पेश कर सके एवं अपने बल पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की पात्रता विकसित कर सके। बिहार में भाजपा का एक नया अध्याय शुरु हो रहा है, सम्राट के भरोसे से।

सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री के रूप में चयन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। वे कोई अप्रत्याशित या अपरिचित चेहरा नहीं हैं। बिहार की राजनीति में सक्रिय रहते हुए, उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए और विभिन्न राजनीतिक धाराओं से गुजरते हुए उन्होंने राज्य की जटिलताओं को निकट से समझा है। उनकी राजनीतिक यात्रा उन्हें एक व्यावहारिक नेता के रूप में स्थापित करती है, जो केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन की वास्तविकताओं से भी जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि उनके नेतृत्व से बिहार की जनता को एक ऐसे प्रशासन की उम्मीद है जो नीतिगत स्पष्टता के साथ-साथ क्रियान्वयन की क्षमता भी रखता हो। किन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि बिहार में नेतृत्व का मूल्यांकन केवल व्यक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी नीतियों, प्राथमिकताओं और परिणामों के आधार पर होता है। पिछले वर्षों में यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से सामने आई है कि शासन की सफलता का निर्धारण केवल मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व से नहीं, बल्कि उस

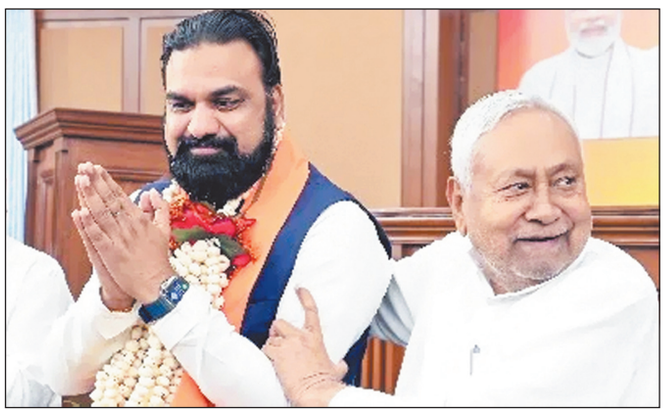

व्यापक नीति-ढांचे से होता है जो केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करता है। भारतीय राजनीति में यह एक नया आयाम है, जहां केंद्र सरकार की नीतियां राज्यों के विकास की दिशा को काफी हद तक प्रभावित करती हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों के उदाहरण इस बात को पुष्ट करते हैं कि अपेक्षाकृत कम चर्चित चेहरों के बावजूद विकास की गति तेज रह सकती है, यदि नीतिगत समर्थन और प्रशासनिक इच्छाशक्ति मजबूत हो।

बिहार के संदर्भ में यह पहलू और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह राज्य लंबे समय तक अवसंरचनात्मक पिछड़ेपन, बेरोजगारी, पलायन और सामाजिक विषमताओं से जूझता रहा है। ऐसे में सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वे इन जटिल समस्याओं के समाधान के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करें। केवल राजनीतिक स्थिरता पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि उसे विकासात्मक स्थिरता में परिवर्तित करना होगा। सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत क्षेत्रों में निरंतर सुधार के साथ-साथ रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना होगा, ताकि बिहार के युवाओं को अपने ही राज्य में अवसर मिल सकें। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि बिहार के हालिया इतिहास में यदि किसी नेता ने प्रशासनिक सुधार और सुशासन की एक स्पष्ट छवि प्रस्तुत की है, तो वह नीतीश कुमार हैं। उन्होंने जिस समय सत्ता संभाली, उस समय बिहार 'जंगलराज' की छवि से जूझ रहा था। कानून-व्यवस्था की स्थिति दयनीय थी, अवसंरचना लगभग ध्वस्त थी और राज्य की छवि राष्ट्रीय स्तर पर नकारात्मक थी। ऐसे समय में नीतीश कुमार ने सड़क, बिजली और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए। विशेष रूप से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइकिल योजना जैसी पहलें सामाजिक परिवर्तन का आधार बनीं। उन्होंने प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे शासन के प्रति जनता का विश्वास पुन: स्थापित हुआ।

नीतीश कुमार का व्यक्तित्व एक संतुलित, संयमित और व्यावहारिक नेता के रूप में उभरता है। वे आक्रामक राजनीति के बजाय संवाद और सहमति की राजनीति के पक्षधर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने राजनीति को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर उठाकर विकास के एजेंडे से जोड़ने का प्रयास किया। हालांकि समय के साथ उनकी राजनीतिक रणनीतियों और गठबंधनों में बदलाव ने उनकी छवि को कुछ हद तक प्रभावित भी किया, लेकिन उनके द्वारा स्थापित प्रशासनिक मानक आज भी बिहार के लिए एक संदर्भ बिंदु बने हुए हैं।

सम्राट चौधरी के लिए यह एक बड़ी चुनौती और अवसर दोनों है कि वे इन स्थापित मानकों को न केवल बनाए रखें, बल्कि उन्हें और आगे बढ़ाएं। उन्हें यह समझना होगा कि बिहार की जनता अब केवल वादों से संतुष्ट नहीं होती, बल्कि परिणाम चाहती है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी भी सुधार की व्यापक संभावनाएं हैं। सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता, उच्च शिक्षा के अवसर, अस्पतालों की स्थिति और चिकित्सकीय सुविधाओं का विस्तार ऐसे क्षेत्र हैं जहां ठोस कार्य की आवश्यकता है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जो किसी भी विकासात्मक प्रयास को कमजोर कर सकती है। यदि सम्राट चौधरी वास्तव में एक प्रभावी और जनोन्मुखी शासन स्थापित करना चाहते हैं, तो उन्हें प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचारमुक्त शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। डिजिटल गवर्नेंस, ई-टेंडरिंग और निगरानी तंत्र को सशक्त बनाकर इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं।

महिला सशक्तिकरण भी बिहार के विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम है। पिछले वर्षों में इस दिशा में कुछ सकारात्मक पहलें हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। यदि सम्राट चौधरी इस क्षेत्र में ठोस और नवाचारी कदम उठाते हैं, तो यह बिहार की प्रगति को एक नई दिशा दे सकता है। पलायन की समस्या भी बिहार के लिए एक स्थायी चुनौती रही है। लाखों लोग रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में जाते हैं, जिससे न केवल राज्य की श्रमशक्ति का क्षरण होता है, बल्कि सामाजिक संरचना पर भी प्रभाव पड़ता है। इस समस्या का समाधान केवल उद्योगों के विकास और स्थानीय रोजगार के अवसरों के सृजन से ही संभव है। कृषि आधारित उद्योग, लघु और मध्यम उद्योग तथा स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देकर इस दिशा में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है।

निश्चिततौर पर यह कहा जा सकता है कि बिहार आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां अतीत के अनुभव, वर्तमान की अपेक्षाएं और भविष्य की संभावनाएं एक साथ उपस्थित हैं। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में यह राज्य किस दिशा में आगे बढ़ेगा, यह उनके निर्णयों, नीतियों और कार्यशैली पर निर्भर करेगा। यदि वे नीतीश कुमार द्वारा स्थापित सुशासन के मानकों को आधार बनाते हुए नवाचार और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं, तो बिहार न केवल अपने पुराने कलंक से पूरी तरह मुक्त हो सकता है, बल्कि एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में भी उभर सकता है। यह समय केवल नेतृत्व परिवर्तन का नहीं, बल्कि सोच और दृष्टिकोण के परिवर्तन का है। बिहार की जनता अब जागरूक है, अपेक्षाएं स्पष्ट हैं और अवसर भी व्यापक हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी के लिए यह आवश्यक है कि वे व्यक्ति-आधारित राजनीति से ऊपर उठकर नीतियों और परिणामों पर केंद्रित शासन प्रस्तुत करें। यदि वे ऐसा कर पाते हैं, तो न केवल वे अपने नेतृत्व को सिद्ध करेंगे, बल्कि बिहार को एक नई पहचान भी देंगे-एक ऐसे राज्य के रूप में जो संघर्ष से उबरकर सफलता की नई गाथा लिखने में सक्षम है।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

(च) ब्रह्महत्या साक्षात् मृत्यु है। (छ) (वह ब्रह्महत्या) आठ पाँव, चार आंख, चार कान, चार ठोड़ी, दो मुख और दो जीभ वाला रूप बना कर ब्रह्मज्य ब्रह्महत्यारे के राष्ट्र को विनष्ट कर डालती है। (ज) वह सब पापों से छूट जाता है, और ब्रह्महत्या से भी उन्मुक्त हो जाता है जो कि अश्वमेध द्वारा यजन करता है। (झ) इन्द्र ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से (वज्र बना कर नन्यानवें वृत्रासुरों को मार डाला ।

पौराणिक स्वरूप

(क) येनावृता इमे लोकास्तमसा त्वाष्टमूर्तिना।
स वै वृत्र इति प्रोक्तः पापः परमदारुणः।।
[(श्रीमद्भागवत 6 ।6।12)
(ख) चिच्छेद युगपद्देवो वज्रेण शतपर्वणा।
दोर्थ्यामुत्कृत्य मूलाभ्यां बभौ रक्तस्रवोऽसुरः ।।26।।]
कृत्वाऽधरां हनुं भूमौ दैत्यो दिव्युत्तरां हनुम्।
नभोगभीरवक्त्रेण लेलिहोल्वणजिह्वया ।।27।।
भित्वा बज्रेण तत्कुक्षि निष्क्रम्य बलभिद् विभुः।
उच्चकर्त शिरः शत्रोगिरिश्टङ्गमिवौजसा।।32।।
(श्रीमद्भागवत 6 । 12)
(ग) ब्रह्महत्या हते तस्मिन्नाससाद वृषाकपिम् ।।10।।
तां ददर्शानुधावन्तीं चाण्डालीमिव रूपिणीम्।
जरया वेपमानाङ्गीं यक्ष्मग्रस्तामसृपटाम्।।12।।
अश्वमेधे महेन्द्रेण विततें ब्रह्मवादिभिः ॥16॥
स वै त्वाष्टवधो भूयानपि पापचयो नृप! ।
नीतस्तेनैव शून्याया नीहार इव भानुना।।20।।
(श्रीमद्भागवत 6 । 13)

अर्थात् (क) जिस अन्धकारमूति त्वष्टा के पुत्र ने इन सब लोकों को ढांप लिया था वही परम दारुण पापी बृत्र नाम वाला असुर था। (ख) इन्द्र ने शतपर्व वज्र सेवृत्र की दोनों भुजाएं काट डालीं। उस समय भुजाओं के कट जाने पर रुधिर से लथ पथ हुवा वृत्र अद्भुत दीख पड़ता था। ।।26।।

क्रमशः ...

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

अनन्या मिश्रा

डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन आजाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। भारतीय इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। वह दर्शनशास्त्र का काफी ज्ञान रखते थे। डॉ सर्वपल्ली ने ही भारतीय दर्शनशास्त्र में पश्चिमी सोच की शुरुआत की थी। वह एक शिक्षक भी थे। आज ही के दिन यानि की 17 अप्रैल को डॉ सर्वपल्ली का निधन हो गया था। उनकी याद में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 20वीं शताब्दी के विद्वानों में उनका नाम सबसे ऊपर है। वह पश्चिमी सभ्यता से अलग हिंदुत्व को देश में बढ़ावा देना चाहते थे। उन्होंने भारत और पश्चिम दोनों में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। वह दोनों सभ्यताओं को मिलाना चाहते थे। उनका मानना था कि देश में सबसे अच्छा दिमाग शिक्षकों का होना चाहिए। क्योंकि देश के निर्माण में शिक्षकों का सबसे अहम योगदान होता है।

राधाकृष्णन जी को साल 1909 में मद्रास प्रेसीडेंसी कॉलेज में दर्शनशास्त्र का अध्यापक बना दिया गया। इसके बाद वह साल 1916 में मद्रास रजिडेसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक अध्यापक बने। वहीं साल 1918 में राधाकृष्णन को मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर चुना गया। फिर वह इंग्लैंड के oxford university में भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक बन गए। राधाकृष्णन शिक्षा को अधिक महत्व देते थे। शाद यही कारण था कि वह इतने ज्ञानी विद्वान बनें। वह हमेशा कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहते थे। जिस कॉलेज से उन्होंने एमए किया था वहीं पर इन्हें बतौर कुलपति नियुक्त किया गया। लेकिन 1 साल बाद ही वह इसको छोड़कर बनारस विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए। राधाकृष्णन ने दर्शनशास्त्र पर कई किताबें भी लिखी हैं।

भारत की स्वतंत्रता के बाद जवाहर लाल नेहरू ने राधाकृष्णन से आग्रह किया कि वह विशिष्ट राजदूत के तौर पर सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों की पूर्ति करें। जिसके बाद उन्होंने नेहरू जी की बात को मानते हुए साल 1947 से 1949 तक संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के तौर पर कार्य किया। संसद में सभी लोग राधाकृष्णन के कार्यों और व्यवहार की प्रशंसा करते थे। वहीं राधाकृष्णन साल 1952 से 1962 तक देश के उपराष्ट्रपति रहे और साल 1962 में वह भारत के राष्ट्रपति बने। बता दें कि राजेंद्र प्रसाद की तुलना में राधाकृष्णन का कार्यकाल काफी चुनौतियों और मुश्किलों भरा रहा।

डॉ. राधाकृष्णन को शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान के लिए साल 1954 में सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

साल 1962 से राधाकृष्णन के सम्मान में उनके जन्मदिन यानि की 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की घोषणा की गई।

साल 1962 में उन्हें ब्रिटिश एकेडमी का सदस्य बनाया गया।

इंग्लैंड सरकार द्वारा राधाकृष्णन को ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान प्राप्त हुआ।

डॉ राधाकृष्णन का निधन एक लम्बी बीमारी के बाद 17 अप्रैल 1975 को हो गया। देश के विकास और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।

महिला आरक्षण बिल के बाद बदलेगी संसद की सूरत

सौरभ वार्ष्णेय

16 अप्रैल से संसद का विशेष संत्र आयोजित होने जा रहा है। इस सत्र में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। लंबे इंतजार और व्यापक राजनीतिक विमर्श के बाद पारित हुआ महिला आरक्षण बिल—जिसे आधिकारिक रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है—देश की संसद और विधानसभाओं की संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करता है, जो भारतीय राजनीति में लैंगिक संतुलन की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।

आज तक भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारी सीमित रही है। हालांकि इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज और ममता बनर्जी जैसी प्रभावशाली महिला नेताओं ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन कुल संख्या के लिहाज से महिलाएं अब भी कम प्रतिनिधित्व वाली श्रेणी में रही हैं। ऐसे में यह आरक्षण बिल केवल संख्या बढ़ाने का नहीं, बल्कि नीति निर्माण में महिलाओं की दृष्टि और संवेदनशीलता को शामिल करने का प्रयास भी है।

इस विधेयक के लागू होने के बाद संसद की सूरत में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकता है। अधिक संख्या में महिला सांसदों की भागीदारी से सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और पोषण जैसे मुद्दों पर अधिक गंभीरता से चर्चा होने की संभावना है। इससे नीतियां अधिक समावेशी और जमीनी हकीकत के करीब बन सकती हैं।

हालांकि, इस बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी। राजनीतिक दलों को योग्य महिला उम्मीदवारों को तैयार करने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में ठोस प्रयास करने होंगे। केवल आरक्षण से ही वास्तविक सशक्तिकरण संभव नहीं है; इसके लिए सामाजिक मानसिकता में बदलाव और राजनीतिक प्रशिक्षण भी उतना ही आवश्यक है।

इसके अलावा, आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी, जो इस कानून के क्रियान्वयन को प्रभावित कर सकती है। इस कारण, इसके प्रभावी लागू होने में समय लगने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।फिर भी, यह कहना गलत नहीं होगा कि महिला आरक्षण बिल भारतीय लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधिक, संतुलित और संवेदनशील बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। यह न केवल संसद की सूरत बदलेगा, बल्कि राजनीति की सोच और प्राथमिकताओं को भी नई दिशा देगा। यह विधेयक केवल महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि एक मजबूत, समावेशी और न्यायपूर्ण भारत के निर्माण की आधारशिला रखता है।

केंद्र सरकार ने हाल ही में उन आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया है, जो 2029 तक विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने के लिए प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को लेकर विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्यों में उभर रही हैं। यह मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि संघीय ढांचे, प्रतिनिधित्व के संतुलन और लोकतांत्रिक विश्वास से भी जुड़ा हुआ है।महिला आरक्षण का उद्देश्य राजनीति में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। लंबे समय से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही है। ऐसे में 33त्न आरक्षण का प्रावधान एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। लेकिन इसके साथ जुड़ा परिसीमन का सवाल कई जटिलताओं को जन्म देता है।

परिसीमन का अर्थ है जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। 2026 के बाद होने वाली संभावित परिसीमन प्रक्रिया में जनसंख्या के वर्तमान आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा। यहीं से दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता शुरू होती है। इन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में जनसंख्या वृद्धि अधिक रही है। ऐसे में आशंका है कि परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों की सीटें घट सकती हैं, जिससे उनकी राजनीतिक ताकत कमजोर हो सकती है।

केंद्र सरकार का कहना है कि महिला आरक्षण और परिसीमन दो अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं, और किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि संतुलन और न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल आश्वासन से राज्यों की चिंताएँ दूर हो जाएंगी? यह भी समझना जरूरी है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोडने का प्रावधान क्यों रखा गया। इसका एक कारण यह है कि नए सिरे से सीटों का निर्धारण होने पर आरक्षित सीटों का संतुलित और न्यायसंगत वितरण संभव हो सके। लेकिन यही प्रावधान अब राजनीतिक विवाद का कारण बन रहा है।

समाधान के लिए आवश्यक है कि केंद्र और राज्यों के बीच संवाद और विश्वास कायम रखा जाए। एक ऐसा मॉडल विकसित किया जाए, जिसमें महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए क्षेत्रीय संतुलन भी बना रहे। संभव है कि परिसीमन के लिए केवल जनसंख्या ही नहीं, बल्कि अन्य मानकों को भी शामिल किया जाए, ताकि न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।महिला आरक्षण एक सामाजिक और लोकतांत्रिक आवश्यकता है, लेकिन इसे लागू करने की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी क्षेत्र या राज्य के साथ असमानता की भावना पैदा न करे। यह समय राजनीतिक परिपक्वता और दूरदर्शिता दिखाने का है, ताकि देश एक समावेशी और संतुलित लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ सके।

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की अनिवार्यता है। लंबे समय से राजनीति और नीति-निर्माण के केंद्र में पुरुषों का वर्चस्व रहा है, जिसके कारण महिलाओं से जुड़े कई मुद्दे अपेक्षित प्राथमिकता नहीं पा सके। ऐसे में महिला आरक्षण का प्रश्न केवल प्रतिनिधित्व का नहीं, बल्कि बराबरी और सशक्तिकरण का भी है।महिलाएं देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी अभी भी सीमित है। पंचायत स्तर पर आरक्षण लागू होने के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि जब महिलाओं को अवसर मिलता है, तो वे न केवल प्रभावी नेतृत्व करती हैं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव भी लाती हैं। इस अनुभव को उच्च स्तर की राजनीति में लागू करना समय की मांग है।महिला आरक्षण सामाजिक असमानताओं को दूर करने का एक प्रभावी माध्यम बन सकता है। भारतीय समाज में अब भी कई स्तरों पर लैंगिक भेदभाव मौजूद है, जो महिलाओं की प्रगति में बाधा बनता है। आरक्षण नीति उन्हें एक सशक्त मंच प्रदान करती है, जहां वे अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती हैं और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं।लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व हो। यदि आधी आबादी निर्णय-निर्माण प्रक्रिया से बाहर रहती है, तो लोकतंत्र अधूरा ही रहेगा। महिला आरक्षण इस अधूरेपन को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।हालांकि, इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं, जैसे राजनीतिक दलों की इच्छाशक्ति, आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन और वास्तविक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद, महिला आरक्षण का महत्व कम नहीं होता।

आज का इतिहास

1875 सर नेविले चैंबरलिन ने स्नूकर का अविष्कार किया।
1876 फ्रेंड्स अकादमी की स्थापना गइडन फ्रॉस्ट द्वारा लोकस्ट वैली न्यूयॉर्क में हुई।
1895 जापान और चीन के बीच शिमोनोसेकी का समझौता हुआ।
1907 ब्राजील एक खूंखार युद्धपोत पर निर्माण शुरू करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया, जिसने एक बहुत ही महंगी दक्षिण अमेरिकी नौसैनिक हथियारों की दौड़ को जन्म दिया।
1912 रूसी साम्राज्य की सेना के सैनिकों ने लीना नदी के पास पूर्वोत्तर साइबेरिया में हड़ताली स्वर्णकारों पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 150 लोगों की मौत हो गई।
1941 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूगोस्लाविया ने जर्मनी के समक्ष आत्मसमर्पण किया।
1942 द्वितीय विश्व युद्ध-बंद फ्रांसीसी जनरल हेनरी जिराउड कोनिस्टीन कैसल में जर्मन कैद से भाग गया।
1946 सीरिया ने फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल की।
1951 पीक जिले को यूनाइटेड किंगडम में पहला राष्ट्रीय उद्यान नामित किया गया था।
1961 क्यूबा द्वारा निर्वासित कास्त्रो को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से ष्ट्ठ द्वारा समर्थित सशस्त्र क्यूबा के निर्वासित क्यूबा, क्यूबा की खाड़ी में घुसपैठ कर रहा था।
1969 सरहान सरहन को यूनाइटेडस्टेट्स के सीनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी की हत्या का दोषी ठहराया गया था।
1971 मिस्र, लीबिया और सीरिया ने मिलकर यूनाइटेड अरब स्टेट बनाने के लिए संघ का गठन किया।
1971 पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश का गठन 1971 में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व शेख मुजीब उर-रहमान ने किया था।
1973 जॉर्ज लुकास ने द स्टार वार्स नामक एक 13-पृष्ठ फिल्म उपचार लिखना शुरू किया।
1975 पोल पॉट के तहत खमेर रूज ने कम्बोडियन गृहयुद्ध को समाप्त करने, नोम पेन्ह पर कब्जा कर लिया और डेमोक्रेटिक कम्पुचिया की स्थापना की।
1993 अंतरिक्ष यान एसटीएस-56 डिस्कवरी धरती पर वापस लौटा।
1994 लिटिल मोर मैजिक न्यूयॉर्क शहर के बेलास्को थिएटर में बंद था। यह 30 दिनों तक हाउसफुल चला।
1994 गोधूलि न्यूयॉर्क शहर के कॉर्ट थियेटर में जारी किया गया था। यह 72 दिनों तक हाउसफुल चला।
1995 पाकिस्तान में बाल मज़दूरी को समाप्त करने वाले युवा कार्यकर्ता इक़बाल मसीह की हत्या।
2000 तुआंकू सैयद सिराजुद्दीन पर्लिस के राजा बने।

हिंदुस्तान की सियासत में महिलाओं के अच्छे दिन

प्रियल भारद्वाज

स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में अभी तक एक महिला प्रधानमंत्री और करीब 15 महिला मुख्यमंत्री रही हैं। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में उच्च राजनीति पद पर महिलाओं की भागीदारी का ये आंकड़ा अपने आप एक दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है। लेकिन, क्या अब समय बदलने वाला है?

दरअसल, सरकार ने 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है, ताकि महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन विधेयकों को पारित किया जा सके और महिलाओं के आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023) को जल्द से जल्द लागू किया जा सके। इस कानून के अमल में आते ही महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अनिवार्य रूप से बढ़नी तय है और जब भागीदारी बढ़ेगी तो उच्च पदों पर अधिक संख्या में उनका पहुंचना तय हो जाएगा।

स्वतंत्रता के तुरंत बाद जब भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्वीकार किया, तब इसे कई पश्चिमी देशों की तुलना में एक क्रांतिकारी कदम माना गया। खासकर शिक्षा और गरीबी के स्तर को देखते हुए। इस अग्रिम शुरुआत के बावजूद महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी व्यवहार में बहुत असमान रही है। हाल ये कि 1952 में जब पहली बार देश में लोकसभा चुनाव हुए, तब कई महिलाओं ने वोट भी नहीं डाला था।

दरअसल, निर्वाचन आयोग के अधिकारी जब मतदाता सूची बना रहे थे, तब लाखों महिलाओं ने अपना नाम बताने से इंकार कर दिया क्योंकि तब उनकी पहचान फलां की पत्नी या फलां की बेटी के रुप में ही जानी जाती थी। मतलब उनकी पहचान किसी पुरुष पारिवारिक सदस्य से जुड़ी होती थी। ऐसे में महिलाओं की राजनीति में सक्रिय भागीदारी दूर की कौड़ी थी।

जैसे-जैसे लोकतंत्र समाज के भीतर गहराई तक पहुंचा, महिलाएं राजनीतिक विमर्श में दिखाई देने लगीं लेकिन सच यही है कि वे अब भी हाशिए पर ही हैं। एक संरचनात्मक बदलाव 1990 के दशक की शुरुआत में पंचायती राज और स्थानीय निकाय कानूनों के लागू होने से आया। इन कानूनों ने स्थानीय निकायों में 33त्न सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कीं। इससे लाखों महिलाओं को पहली बार राजनीतिक सत्ता का अनुभव मिला, भले ही 'प्रधान पति' या 'पार्षद पति' के रूप में प्रॉक्सी राजनीति की मौजूदगी मजबूत बनी रही।

1990 के दशक में ही एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन और संभव था, लेकिन राजनीतिक दलों के स्वार्थ ने उसे संपन्न नहीं होने दिया। 1996 में देवगौड़ा सरकार ने पहली बार महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया था। इसमें संसद और विधानसभाओं में 33त्न आरक्षण का प्रस्ताव था। लेकिन भारी विरोध के कारण यह पास नहीं हो सका और लोकसभा भंग होने के साथ ही बिल खत्म हो गया। फिर 1998, 1999, 2002, 2003 में भी अलग-अलग सरकारों ने इसे पेश करने की कोशिश की।

हर बार जबरदस्त हंगामा हुआ और बिल ठंडे बस्ते में चला गया। एक बार तो संसद में लालू यादव एंड टीम के सांसदों द्वारा बिल की कॉपी छीनकर फाड़ने और स्पीकर की टेबल तक पहुंचने जैसी घटनाएं हुईं। ये भारतीय संसद के सबसे उग्र दृश्यों में से एक माना जाता है। 2010 में मनमोहन सिंह सरकार के दौरान यह बिल राज्यसभा में पास हो गया। लेकिन लोकसभा में पेश नहीं हो पाया, इसलिए कानून नहीं बन सका।

इसका सीधा अर्थ है कि कोशिश तो हुई, लेकिन परवान नहीं चढ़ पाईं क्योंकि इस कानून को पास कराने के लिए जिस राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता थी, वो उस तरह कोई सरकार नहीं दिखा पाई, जैसी नरेंद्र मोदी सरकार ने दिखाई। सितंबर 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे नए रूप में पेश किया और लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होकर यह कानून बन गया यानी नारी वंदन अधिनियम, 2023 । अब इसे लागू करने की तैयारी है।

इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी तेजी से बढ़ी है। 2009 के लोकसभा चुनाव में जहां लगभग 55ङ्क56त्न महिलाओं ने वोट डाला था, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 65ङ्क67 फीसदी महिलाओं ने वोट डाला। बीते लोकसभा चुनाव में बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य ऐसे भी थे, जहां महिला वोट का प्रतिशत पुरुषों से कुछ अधिक रहा।

उच्च स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की बात करें तो पहली लोकसभा में कुल 5 फीसदी महिला सांसद थीं, जो इंदिरा गांधी के आखिरी कार्यकाल यानी 1980 के वक्त सातवीं लोकसभा में भी 5 फीसदी ही रहीं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, उस 16वीं लोकसभा में 62 महिलाएं लोकसभा पहुंची थीं यानी करीब 11.4 फीसदी। 2024 में ये प्रतिशत 13.6 फीसदी है। अब नारी वंदन अधिनियम, 2023 लागू होने के बाद कम से कम 33 फीसदी महिला सांसद दिखेंगी और आधी आबादी के राजनीतिक हस्तक्षेप को मान्यता मिलेगी।

दरअसल, बीते 12 साल में महिलाएं एक लक्षित चुनावी वर्ग बन गई हैं और सभी राजनीतिक दलों ने उनके लिए विशेष कार्यक्रम और प्रोत्साहन योजनाएं बनानी शुरू की हैं। एलपीजी कनेक्शन, नकद हस्तांतरण, महिला सुरक्षा, घरेलू उपयोग की वस्तुएं जैसे मिक्सी आदि चुनावी वादों का हिस्सा बनने लगे हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ने पुरुष मध्यस्थों पर निर्भरता को कम किया है। केंद्र और राज्य सरकारों ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के एक अलग राजनीतिक वर्ग का निर्माण और पोषण किया है। अगर बिहार ने महिलाओं के वोट को आकर्षित करने के लिए शराबबंदी का रास्ता अपनाया, तो मध्य प्रदेश में 'लाड़ली बहना' जैसी योजनाएं सामने आई हैं।

हालांकि महिलाओं ने राजनीतिक क्षेत्र में काफी हद तक अपनी भूमिका और अधिकार स्थापित किए हैं, फिर भी प्रतिनिधित्व में एक स्थायी अंतर बना हुआ है। संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी लगभग 14% है और उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पुरुष-प्रधान बनी हुई है। इसके अलावा, महिलाओं के अपने उचित स्थान तक पहुंचने में कई चुनौतियां बनी हुई हैं। संरचनात्मक बाधाएं हैं, जैसे कि पार्टी टिकट वितरण पुरुषों के पक्ष में झुका हुआ है और चुनावी वित्त अब भी पुरुषों के नियंत्रण में है। सामाजिक बाधाएं भी स्पष्ट हैं, जैसे कि एक महिला राजनेता को घरेलू जिम्मेदारियों और राजनीतिक जीवन के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा महिलाओं की व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़ा है। लेकिन, अब वक्त बदलने वाला है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 निश्चित रूप से महिला नेताओं का एक सशक्त समूह तैयार करेगा और हमारी राजनीतिक संस्कृति को पुनर्परिभाषित करेगा। चुनाव प्रचार के तरीकों में स्पष्ट बदलाव आएंगे और महिलाएं पार्टी टिकट वितरण तथा चुनावी वित्त पर भी प्रभाव डाल सकेंगी। यह कहना उचित होगा कि नीतिगत प्राथमिकताओं में भी बदलाव आएगा, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थिरता, कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी और लैंगिक भेदभाव जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

होर्मुज: किसी के लिए रास्ता किसी के लिए किस्मत!

जाहिद खान

नक्शे में होर्मुज एक पतली सी लकीर लगता है, लेकिन असल में यही वह दरवाजा है, जहां से दुनिया की अर्थव्यवस्था सांस लेती है। यहां हलचल बढ़े तो तेल महंगा हो जाता है। तनाव बढ़े तो बाजार डगमगा जाते हैं और अगर यह रास्ता रुक जाए तो कई मुल्कों की जिंदगी थम सकती है, लेकिन एक बात और है, जो कम लोग समझते हैं। यह रास्ता सबके लिए बराबर नहीं है। कुछ के पास विकल्प हैं और कुछ के लिए यही सब कुछ है।

होर्मुज को समझना है तो पहले यह समझो कि यह जगह है क्या। ऊपर ईरान, नीचे ओमान और उसके पास संयुक्त अरब अमीरात और बीच में एक पतला सा समुद्री रास्ता। यही रास्ता फारस की खाड़ी को बाहर की दुनिया से जोड़ता है। खाड़ी के अंदर जितना तेल है, उसका बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से बाहर निकलता है। आंकड़ा सीधा है। दुनिया के कुल तेल का करीब पांचवां हिस्सा रोज इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, अमीरात और ईरान का तेल यहीं से निकलकर भारत, चीन, जापान, यूरोप और दूसरी जगहों तक पहुंचता है। यानी एक तरफ खाड़ी के मुल्क हैं और दूसरी तरफ पूरी दुनिया और दोनों के बीच यह एक ही दरवाजा है। लेकिन अब असली फर्क समझें। ओमान इस पूरे खेल में सबसे अलग है। वह खुद इस रास्ते के बाहर बैठा है, सीधे समुद्र से जुड़ा हुआ। उसे अपने कारोबार के लिए होर्मुज पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। रास्ता बंद हो भी जाए तो ओमान की रफ्तार नहीं रुकती। संयुक्त अरब अमीरात ने भी पहले से तैयारी कर रखी है। उसने अपने तेल को एक अलग पाइपलाइन के जरिए फुजैरा तक पहुंचाने का इंतजाम किया है। फुजैरा ऐसा बंदरगाह है, जो इस रास्ते के बाहर है यानी जरूरत पड़ने पर अमीरात बिना होर्मुज के भी अपना तेल दुनिया तक भेज सकता है। सऊदी अरब और भी आगे की सोच रखता है। उसने अपने देश के अंदर से तेल को दूसरी तरफ लाल सागर तक पहुंचाने का रास्ता बना लिया है। वहां से जहाज सीधे बाहर निकल जाते हैं यानी उसके पास दो रास्ते हैं। एक बंद हो तो दूसरा खुला है।

अब उन मुल्कों को देखो जिनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इराक, कुवैत, कतर और खुद ईरान। ये सब फारस की खाड़ी के अंदर हैं। इनके पास बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वह है होर्मुज। अगर यह दरवाजा बंद हो जाए तो इनका तेल, इनका कारोबार, सब कुछ वहीं रुक जाएगा। इसे ऐसे समझें, जैसे किसी घर का सिर्फ एक ही दरवाजा हो। अगर वह बंद हो गया तो अंदर का सब कुछ अंदर ही रह जाएगा। यही हालत इन देशों की है। यही वजह है कि होर्मुज सिर्फ पानी का रास्ता नहीं है, यह ताकत का खेल है। जिसके पास विकल्प है वह थोड़ा संभला रहता है और जिसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उसके लिए यह जिंदगी और कारोबार दोनों का सवाल बन जाता है।

दुनिया के बड़े देश इस रास्ते को हर हाल में खुला रखना चाहते हैं क्योंकि यहां रुकावट का मतलब है पूरी दुनिया में तेल की कमी और कीमतों में उछाल। दूसरी तरफ ईरान इस जगह के बेहद करीब बैठा है और उसे पता है कि यह उसकी सबसे बड़ी ताकत है इसलिए जब भी तनाव बढ़ता है, होर्मुज का नाम सबसे पहले सामने आता है। हाल के हालात ने फिर यही दिखाया। जहाजों की आवाजाही धीमी हुई है। कई जगह रुकावट आई और दुनिया को फिर याद आया कि यह छोटा सा रास्ता असल में कितना बड़ा असर रखता है। सीधी बात यह है कि होर्मुज को समझना मतलब सिर्फ नक्शा देखना नहीं है। यह समझना है कि दुनिया कैसे चलती है, तेल कैसे पहुंचता है और कैसे एक पतली सी लकीर बड़े-बड़े फैसलों को बदल देती है।

धोखा फरेब नाकामी की पटकथा रही इस्लामाबाद वार्ता

मनोज कुमार अग्रवाल

करीब डेढ़ महीने से से अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुई इस्लामाबाद वार्ता बेनतीजा खत्म हो गई। 21 घंटे की चर्चा के बावजूद ईरान और अमेरिका में आपसी सहमति नहीं बन पाई तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने लाव-लश्कर के साथ अमेरिका वापस लौट गए और जाते-जाते कह गए कि यह ईरान के लिए बुरी खबर है कि कोई समझौता नहीं हुआ। लेकिन जो ईरान 28 फरवरी को अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की शहादत से लेकर मिनाब में डेढ़ सौ बच्चियों की जान जाने तक कई बुरी खबरों को झेलकर भी अपनी शर्तों पर टिका हुआ है, उसे अमेरिका भला एक वार्ता के विफल होने से क्या हिला पाएगा। असल में तो इस्लामाबाद वार्ता की असफलता अमेरिका के लिए बुरी खबर है, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य की चाबी अब भी ईरान के हाथ में ही है और इससे भी बढ़कर उसके पास सिर न झुकाने का जो जज्बा है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के पास नहीं है। ट्रंप नेतन्याहू की मर्जी से युद्ध छेड़ते हैं और समझौता भी नहीं कर पाते, क्योंकि नेतन्याहू ऐसा नहीं चाहते।

आपको बता दें बीते दिनों न्यूयार्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें बताया गया कि बेंजामिन नेतन्याहू 11 फरवरी को अमेरिका में थे, जहां उन्होंने ट्रंप के सामने एक पूरी रणनीति बताई थी कि ईरान पर हमला करना चाहिए, क्योंकि वह अभी कमजोर है। इससे ईरान में सत्ता बदली जा सकती है और उसके संसाधनों पर कब्जा भी किया जा सकता है। नेतन्याहू ऐसे ही प्रस्ताव पहले बराक ओबामा, जो बाइडेन और जार्ज बुश को भी दे चुके थे, लेकिन इन तीनों राष्ट्रपतियों ने अपने कार्यकाल में ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। यह खुलासा पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी ने हाल ही में किया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू की बात मानने को मजबूर हो गए। क्या इसके पीछे एपस्टीन फाइल्स के खुलासे हैं, इस सवाल का जवाब अभी मिलना बाकी है। बहरहाल, यह वार्ता बेनतीजा रही, क्योंकि एक तरफ इजरायल लेबनान पर अपने हमले नहीं रोक रहा था, जबकि ईरान की 10 शर्तों में यह एक अहम शर्त थी कि लेबनान पर हमले रुकने चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपने

रुख में इंच भर का बदलाव नहीं दिखाया।

अमेरिका-ईरान वार्ता बिना नतीजे के खत्म हो गई. लेकिन बातचीत के नाम पर असली फायदा डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया है। अमेरिका ने होर्मुज में माइंस हटाने वाले जहाज भेज दिए हैं। वहीं पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब में जेट भेजे हैं। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या बातचीत के नाम पर ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई गई. कहीं बातचीत में उलझाकर उसे फिर से धोखा तो नहीं दिया गया। क्योंकि बातचीत के बीच ही अमेरिका ने माइंस हटाने के लिए अपने दो सैन्य जहाजों को होर्मुज के पार ईरान के पास भेज दिया है। करीब 21 घंटे तक चली मैराथन बातचीत के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को खाली हाथ लौटना पड़ा। वेंस ने साफ कहा कि अमेरिका ने अपनी 'रेड लाइन' बता दी थी, लेकिन ईरान ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया. दूसरी तरफ ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने जरूरत से ज्यादा शर्तें थोप दीं और बातचीत को संतुलित नहीं रखा.

यहां यह भी गौरतलब है कि दोनों पक्षों के बीच 5 अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इनमें होर्मुज जलडमरूमध्य, परमाणु कार्यक्रम, युद्ध की भरपाई, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाना और ईरान के खिलाफ तथा पूरे क्षेत्र में चल रहे युद्ध को पूरी तरह खत्म करने जैसे विषय शामिल रहे। लेकिन इन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। अमेरिका न ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने के लिए तैयार हुआ, न उसने होर्मुज पर अपना रुख साफ किया। दरअसल पिछले दस दिनों में ही ट्रम्प दो बिल्कुल अलग-अलग बातें कह चुके हैं। पहले उन्होंने कहा था कि होर्मज में अमेरिका की कोई खास दिलचस्पी नहीं है, अमेरिका को वहां से गुजरने वाले तेल की जरूरत नहीं है। फिर कुछ ही दिनों बाद उन्होंने कहा कि यह अमेरिका की मांगों का सबसे जरूरी हिस्सा है, और अगर इसे खुला नहीं रखा गया तो कोई बातचीत नहीं हो सकती। वैसे यह तय है कि होर्मुज बनारसमध्य पर अमेरिका अपना कब्जा चाहता है, क्योंकि ईरान ते इस पर न केवल नाकेबंदी की है, बल्कि अब शुल्क चिनेको एरुआत भी कर दी है और ट्रंप इससे बुरी तरह गए हैं। ईरानी संसद से मंजूरी मिलने के बाद अब नामिरिखोलूश्यनरी गाईस कॉर्पस को होर्मुज से गुजरने पाहा से शुल्क वसूलने का अधिकार मिल गया है। एक बेरल तेल पर एक डॉलर ईरान वसूलेगा, साथ ही क्रिप्टो करेंसी में भुगतान की व्यवस्था भी होगी, ताकि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का कोई असर न पड़े। ईरान की इस रणनीति से उसे आर्थिक मजबूती मिलेगी, अमेरिका को इस बात का अहसास हो चुका है। इसलिए अब उसने फिर से अपने पत्ते फेंटने शुरु किए हैं, ताकि युद्ध को जायज ठहरा सके।

हालांकि इस युद्ध ने एक तरफ ईरान और खाड़ी देशों समेत पूरी दुनिया में घोर तबाही मचाई है, वहीं एक नयी वैश्विक व्यवस्था भी तैयार की है, जिसमें ईरान निस्संदेह एक आदर्श की तरह उभरा है। ईरान ने संदेश दे दिया है कि महाशक्ति की अवधारणा और उसके हौव्वे को आत्मबल से कैसे तोड़ा जा सकता है। अब अन्य देशों को भी यह प्रेरणा मिली है कि वे अमेरिकी शर्तों के आगे झुकने से इंकार करने की हिम्मत दिखाएं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए. यह तैनाती दोनों देशों के रक्षा समझौते के तहत की गई, लेकिन इसे ईरान के लिए एक सख्त संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है. यह अमेरिका की दोहरी रणनीति थी ताकि एक तरफ बातचीत के जरिए समाधान का दिखावा किया जाए, दूसरी तरफ सैन्य दबाव बनाकर अपनी शर्तें मनवाई घटनाक्रम की तुलना 28 फरवरी की उस घटना से भी की जा रही है, जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया था. यह हमला ऐसे समय में किया गया था जब दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी. जब किसी को हमले की उम्मीद नहीं थी तब ईरान पर अटैक हुआ, जिसमें सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे गए. इस बात का खतरा पहले से था कि कहीं अमेरिका बातचीत के बीच धोखा न दे दे वही हुआ अब ईरान को और मजबूती से खड़े होने की जरूरत होगी।

परिसीमन मुद्दे पर उत्तर बनाम दक्षिण का नैरेटिव

नीरज कुमार दुबे

केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच परिसीमन को लेकर छिड़ा विवाद अब राजनीतिक टकराव के नए चरण में पहुंच चुका है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा राज्य भर में काला झंडा प्रदर्शन की घोषणा ने इस मुद्दे को और अधिक तीखा बना दिया है। यह विवाद उत्तर और दक्षिण के बीच राजनीतिक शक्ति संतुलन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कई सवाल खड़े करता है।

देखा जाये तो परिसीमन का अर्थ है जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का पुनर्निर्धारण और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्गठन। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार यह प्रक्रिया प्रत्येक जनगणना के बाद होनी चाहिए। वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटें 1971 की जनगणना पर आधारित हैं, क्योंकि लंबे समय से परिसीमन पर रोक लगी हुई थी ताकि जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों को नुकसान नहीं हो। अब केंद्र सरकार इस रोक को हटाकर 2011 की जनगणना के आधार पर नई व्यवस्था लागू करना चाहती है और सीटों की संख्या को बढ़ाकर लगभग 850 तक करने का प्रस्ताव है।

केंद्र का तर्क है कि देश की जनसंख्या संरचना में भारी बदलाव आया है और प्रतिनिधित्व को वास्तविक स्थिति के अनुरूप बनाया जाना आवश्यक है। साथ ही महिला आरक्षण को लागू करने के लिए भी यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन दक्षिण के कई नेता इस प्रस्ताव को संदेह की नजर से देख रहे हैं।

एमके स्टालिन ने इसे दक्षिणी राज्यों के खिलाफ पक्षपात बताया है। उनका कहना है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई, उन्हें इस प्रक्रिया के जरिए दंडित किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार ने उनकी चिंताओं को नजरअंदाज किया तो उसे भारी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने इस मुद्दे को केवल तमिलनाडु का नहीं बल्कि संघीय ढांचे की रक्षा का सवाल

बताया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी इस प्रस्ताव पर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक शक्ति को कमजोर कर सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि एक संतुलित मॉडल अपनाया जाए जिसमें जनसंख्या के साथ-साथ आर्थिक योगदान को भी ध्यान में रखा जाए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी चेतावनी दी है कि यह प्रक्रिया कुछ बड़े राज्यों के पक्ष में शक्ति का केंद्रीकरण कर सकती है और संघीय संतुलन को बिगाड़ सकती है।

देखा जाये तो यहां तक तो बहस एक लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा लगती है, लेकिन जिस तरह से इसे उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, वह चिंताजनक है। भारत एक संघीय गणराज्य है जहां सभी राज्यों की समान भागीदारी और राष्ट्रीय एकता सर्वोपरि है। ऐसे में क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काना और राजनीतिक लाभ के लिए विभाजन की रेखाएं खींचना एक गलत मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम का बयान भी कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने दावा किया कि परिसीमन से दक्षिणी राज्यों की आवाज दब जाएगी और संसद सत्र को चुनाव के समय बुलाना एक सुनियोजित साजिश है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसे समय समय पर लागू किया जाना आवश्यक है। इसे साजिश या राजनीतिक चाल बताना क्या देश की संस्थाओं पर अनावश्यक संदेह पैदा नहीं करता?

चिदंबरम जैसे वरिष्ठ नेता, जो देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह तथ्यों और संतुलित दृष्टिकोण के साथ अपनी बात रखें। यदि तमिलनाडु की सीटें बढ़कर 39 से 58 तक पहुंच सकती हैं, जैसा उन्होंने स्वयं कहा, तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि राज्य की आवाज पूरी तरह दब जाएगी? यह तर्क स्वयं में विरोधाभासी प्रतीत होता है।

दरअसल, इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का मूल सिद्धांत नहीं है? यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या अधिक है, तो उसका प्रतिनिधित्व भी अधिक होना स्वाभाविक है। साथ ही यह भी सही है कि विकास और जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए इस मुद्दे पर संतुलित और व्यावहारिक समाधान की आवश्यकता है, न कि राजनीतिक ध्रुवीकरण की। दक्षिणी राज्यों के नेताओं को चाहिए कि वह इस विषय पर संवाद और सहमति की दिशा में आगे बढ़ें, न कि विरोध और टकराव की राजनीति को बढ़ावा दें। केंद्र सरकार को भी सभी राज्यों की चिंताओं को गंभीरता से सुनते हुए ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जो न्यायसंगत और सर्वमान्य हो।राजनीति यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने घोषणा की है कि ढ्ढहृष्ठढ्ढ ब्लॉक के तहत एकजुट विपक्षी दल संसद में प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का कड़ा विरोध करेंगे। नई दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में विपक्षी नेताओं की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में खरगे ने कहा कि यह विधेयक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को कमजोर कर सकता है और सरकार ने इसे बिना जनगणना पूरी किए पेश किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यपालिका संवैधानिक संस्थाओं की शक्तियों को अपने हाथ में ले रही है और परिसीमन के जरिए कभी भी सीमाओं में बदलाव कर सकती है।

नेपाल के प्रधानमंत्री ने चौंकाया भारत को

सनत जैन

महज 36 साल की उम्र में नेपाल के प्रधानमंत्री बने बालेन शाह ने शपथ लेते ही जिस तरह से अपनी सक्रियता दिखाई है, उसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा उनकी भारत में हो रही है। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में युवा लोगों को रखा है। नेपाल के पुराने धाकड़ राजनेता और राजवंश कहां चला गया, वह ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। बालेन शाह की कैबिनेट में शामिल सभी मंत्री उच्च शिक्षित और विशेषज्ञ हैं। मंत्रिमंडल की औसत आयु 38.21 वर्ष है। मंत्रिमंडल में 5 महिला मंत्रियों को स्थान दिया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री की कैबिनेट पूरी तरह से जेन-जी आंदोलन से निकलकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंची है। भारत सहित विश्व के अन्य देशों में जिस तरह से नेपाल सरकार की चर्चा हो रही है। सरकार जिस तरह से काम कर रही है। उसकी प्रशंसा इन दिनों सारी दुनिया के जेन-जी में देखने को मिल रही है। नेपाल में पहली बार पारंपरिक राजनीति से हटकर युवाओं ने अपनी सरकार बनाई है। सरकार को लेकर विशेषज्ञता और समर्पण को महत्व देते हुए जिस तरह से कार्य करना शुरू किया है, उससे आशा की एक नई किरण देखने को मिल रही है। शपथ लेने के दूसरे दिन ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भिजवा दिया। कठोर से कठोर निर्णय लेने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। विदेशों में नेताओं और अधिकारियों के जमा काले धन को नेपाल वापस लाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। बिना किसी लाग लपेट के प्रधानमंत्री और कैबिनेट के सदस्य नेपाल स्थित विभिन्न देशों के दूतावास पहुंच रहे हैं। जहां पर वह नेपाल के नए विकास मॉडल को लेकर विभिन्न देशों के राजदूतों से चर्चा कर रहे हैँ। नेपाल की जरूरतों और विकास के लिए त्वरित निर्णय की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नेपाल मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री एक से एक बढ़कर एक हैँ। कोई टेक्नोलॉजी से है, कोई पूर्व मेयर और संगीतकार रह चुका है। 2 मंत्री पीएचडी होल्डर हैं। वित्त मंत्री डा स्वर्णिम अर्थशास्त्र से पीएचडी कर चुकी हैं। विदेश मंत्री शिशर खनाल जिनकी उम्र 47 साल की है वह अमेरिका से पब्लिक पॉलिसी और पॉलिटिकल इकोनॉमी में स्नातक हैं। नेपाल में पढ़े-लिखे लोगों का मंत्रिमंडल है। ऐसा मंत्रिमंडल दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं है। दुनिया के अन्य देशों की तुलना में यह बिल्कुल अलग है। सबसे अच्छी बात यह है, सारे युवा मिलकर नेपाल को नई दिशा देने के लिए अपना अधिक से अधिक समय दे रहे हैं। इनकी ऊर्जा देखने लायक है। जिस तरह से यह सोच समझकर गंभीरता के साथ निर्णय ले रहे हैं। निश्चित रूप से उसके सुखद परिणाम कुछ ही महीनो में दिखना शुरू हो जाएंगे। 2 सप्ताह पुरानी सरकार 100 सूत्री शासन सुधार एजेंडा पेश कर चुकी है। इस एजेंडे पर काम भी शुरू कर दिया है। मंत्रालयों का पुनर्गठन, दक्षिण एशिया संघर्ष के प्रभाव, नेपाल के एनआईआर की सुरक्षा का कार्य, कार्की आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही, संविधान संशोधन, पार्टी आधारित छात्र संघ व्यवस्था समाप्त करने, निजी अस्पतालों में 10 फीसदी मुफ्त बेड गरीबों के लिए। इस तरह स्वास्थ्य एवं रोजगार के लिए जिस तरह से सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, उसको देखते हुए, यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है, यदि यही उत्साह कुछ और समय तक बना रहता है तो आने वाले समय में नेपाल का भविष्य सारी दुनिया के लिए देखने योग्य होगा। नेपाल में अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं। इसके बाद भी जिस तरह से नेपाल मंत्रिमंडल ने अपना एजेंडा लागू कर आम जनता को विश्वास में लिया वह महत्वपूर्ण बात है। नेपाल में सामाजिक, आर्थिक, न्याय, सुशासन, महंगाई और बेरोजगारी के क्षेत्र में जो प्रयास देखने को मिल रहे हैँ, निश्चित रूप से नेपाल युवा पीढ़ी उत्साह में पुरानी बीमारियों को त्याग कर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है। उससे लगता है, नेपाल एक नए वैश्विक स्वरूप में स्थापित होने की दिशा मे सफल होगा। जेन-जी ने जिस तरह से नेपाल की पुरानी सत्ता को उखाड़ कर नई सत्ता को स्थापित किया है, इस बात का असर कहीं ना कहीं अब भारत में भी दिखने लगा है। यहां का युवा भी बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य समस्याओं को लेकर उद्देलित है। भारत के लिए वर्तमान स्थिति में यह चिंताजनक है। भारत की संवैधानिक संस्थाओं को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। भारत की संवैधानिक संस्थाएं सरकार के इशारे पर काम करती हुई दिख रही हैं, जिससे युवाओं में रोष दिन-प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से सबक लेकर इस तरह की स्थितियां भारत में उत्पन्न ना हों, इसके लिए सभी संवैधानिक संस्थाओं को मिलकर आगे आना चाहिए।

अप्रैल में फैमिली के साथ इन शानदार जगहों को बनाएं डेस्टिनेशन पॉइंट, हर पल रहेगा यादगार

अप्रैल साल का एक ऐसा महीना होता है, जब देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ती है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर आप अप्रैल की चिलचिलाती गर्मी में फैमिली के साथ ठंडी-ठंडी जगहों पर पहुंच सकते हैं।

हर कोई परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहता है। इसलिए जब भी लोगों को समय मिलता है, तो वह अपने परिवार के साथ पसंदीदा जगहों पर पहुंच जाते हैं। अप्रैल के महीने में कई लोग अपने परिवार के साथ घूमने-फिरने के लिए निकलते हैं। अप्रैल साल का एक ऐसा महीना होता है, जब देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ती है। गर्मी के कारण लोग फैमिली के साथ ठंडी-ठंडी जगहों पर मौज-मस्ती का प्लान बनाते हैं। लेकिन लोग सही जगह का चुनाव नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर आप अप्रैल की चिलचिलाती गर्मी में फैमिली के साथ ठंडी-ठंडी जगहों पर पहुंच सकते हैं।

मैक्लॉडगंज

अगर आप अप्रैल के महीने में हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में फैमिली संग घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो मैक्लॉडगंज आपके लिए परफेक्ट जगह है। यह हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत और फेमस हिल स्टेशन है। जोकि धर्मशाला से करीब 5 किमी दूर है।

अप्रैल में मैक्लॉडगंज का मौसम सुहावना रहता है। इस दौरान आप अपने परिवार के साथ यहां पर यादगार पल बिता सकते हैं। आप मैक्लॉडगंज में फैमिली के साथ सेंट जॉन चर्च, नड्डी व्यू पॉइंट, भागसूनाग वाटरफॉल और डल झील जैसी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं।

बेताब वैली

जब भी जम्मू-कश्मीर में घूमने की बात होती है, तो लोग सबसे पहले गुलमर्ग, श्रीनगर या फिर सोनमर्ग का नाम लेते हैं। लेकिन आप इन सभी से हसीन बेताब वैली को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह वैली जम्मू-कश्मीर का वह छिपा हुआ खजाना है, जिसकी खूबसूरती देखकर आप खुशी से झूम उठेंगे।

बेताब वैली में घास के मैदान, शांत और शुद्ध वातावरण और झील झरने इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करते हैं। वहीं बॉलीवुड की कई फिल्मों की यहां पर शूटिंग हो चुकी है। अप्रैल के महीने में यहां का तापमान एकदम सुहावना रहता है।

झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता का एक अद्भुत उदाहरण है दशम जलप्रपात

दशम जलप्रपात लगभग 44 मीटर (144 फीट) की ऊँचाई से गिरता है, जिससे यह झारखंड के प्रमुख जलप्रपातों में शामिल है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण और झरने की गूंज पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है।

झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 34 किलोमीटर दूर, तैमारा गाँव के समीप स्थित दशम जलप्रपात (Dassam Falls), राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है, जो सुवर्णरेखा नदी की एक सहायक नदी है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण और झरने की गूंज पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है।

जलप्रपात की विशेषताएँ

ऊँचाई : दशम जलप्रपात लगभग 44 मीटर (144 फीट) की ऊँचाई से गिरता है, जिससे यह झारखंड के प्रमुख जलप्रपातों में शामिल है।

नाम की उत्पत्ति : स्थानीय मुंडारी भाषा में फदाशोंगफ का अर्थ होता है पानी का गिरना। समय के साथ यह शब्द दशम में परिवर्तित हो गया।

प्राकृतिक संरचना : यह जलप्रपात एक निक पॉइंट का उदाहरण है, जहाँ नदी की ढलान में अचानक परिवर्तन होता है, जिससे जलप्रपात का निर्माण होता है।

दृश्य सौंदर्य : जलप्रपात के चारों ओर घने जंगल और चट्टानी क्षेत्र हैं, जो इसे पिकनिक और फोटोग्राफी के लिए आदर्श स्थान बनाते हैं।

कैसे पहुँचें

सड़क मार्ग : रांची से दशम जलप्रपात तक पहुँचने के लिए NH-33 (अब NH-18) का उपयोग किया जा सकता है। अंतिम 10 किलोमीटर की यात्रा गाँव की सड़कों से होती है, जो संकरी लेकिन ड्राइविंग के लिए उपयुक्त हैं।

रेल मार्ग : निकटतम रेलवे स्टेशन रांची है, जहाँ से टैक्सी या बस के माध्यम से जलप्रपात तक पहुँचा जा सकता है।

यात्रा का सर्वोत्तम समय

मानसून (जुलाई से सितंबर)ः इस अवधि में जलप्रपात अपने पूर्ण प्रवाह में होता है, लेकिन भारी वर्षा के कारण फिसलन और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ हो सकती हैं।

शीतकाल (अक्टूबर से फरवरी) : इस समय मौसम सुखद होता है और भीड़ भी कम होती है, जिससे यात्रा अधिक आनंददायक होती है।

सुरक्षा सुझाव

जलप्रपात के नीचे तैराकी या स्नान से बचें, क्योंकि यहाँ की जलधारा तेज होती है और कई दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं।

फिसलन से बचने के लिए उपयुक्त जूते पहनें और बच्चों पर विशेष ध्यान दें।

अपने साथ पानी और हल्का नाश्ता रखें, क्योंकि आसपास सीमित सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

अतिरिक्त जानकारी

प्रवेश शुल्क : नि :शुल्क

पार्किंग : पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ 30 का शुल्क लिया जाता है।

सीढ़ियाँ : जलप्रपात के तल तक पहुँचने के लिए लगभग 300 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं, जो अच्छी तरह से निर्मित हैं।

दशम जलप्रपात, झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता का एक अद्भुत उदाहरण है। यह स्थान न केवल प्रकृति प्रेमियों के लिए, बल्कि फोटोग्राफरों और शांत वातावरण की तलाश करने वालों के लिए भी एक आदर्श गंतव्य है। यदि आप झारखंड की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो दशम जलप्रपात को अपनी सूची में अवश्य शामिल करें।

केरल के मुनरो आइलैंड की खूबसूरती देखकर झूम उठेंगे आप, प्रकृति प्रेमियों के लिए है जन्नत

जब भी केरल घूमने की बात होती है, तो लोग सबसे पहले एलेप्पी, कुमारकोम, मुन्नार, वायनाड, वागामों और त्रिशूर जैसी फेमस जगहों पर जाना चाहते हैं। लेकिन मुनरो द्वीप के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है।

दक्षिण भारत में जब किसी खूबसूरत राज्य में घूमने की बात होती है, तो बहुत सारे लोग केरल का नाम सबसे पहले लेते हैं। केरल दक्षिण भारत का पर्यटन हब माना जाता है। केरल की खूबसूरती हर दिन हजारों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। यहां पर स्थित लैगून और बैकवॉटर देखने के लिए लोग केरल पहुंचते हैं। जब भी केरल घूमने की बात होती है, तो लोग सबसे पहले एलेप्पी, कुमारकोम, मुन्नार, वायनाड, वागामों और त्रिशूर जैसी फेमस जगहों पर जाना चाहते हैं। लेकिन मुनरो द्वीप के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको मुनरो द्वीप की खूबसूरती, खासियत और यहां पर मौजूद कुछ शानदार जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं।

मुनरो द्वीप

केरल के कोल्लम जिले में स्थित मुनरो द्वीप एक अद्भुत और अनोखी जगह है। यह कोल्लम शहर के कुछ किमी की दूरी है। इस द्वीप को कई लोग मुंद्रोथुरुथु के नाम से भी जानते हैं।

केरल में अष्टमुडी झील और कल्लदा नदी के संगम पर यह द्वीप स्थित है। मुनरो द्वीप राजधानी तिरुवनंतपुरम से करीब 90 किमी की दूरी पर है। यह द्वीप एलेप्पी से करीब 87 किमी दूर और कोट्टयम से महज 84 किमी दूर है।

मुनरो द्वीप का इतिहास

मुनरो द्वीप का इतिहास काफी रोचक है। इस आइलैंड के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम पूर्व ब्रिटिश निवासी कर्नल मुनरो के नाम पर रखा गया है। बताया जाता है कि जब कर्नल मुनरो ने देखा कि सिंचाई के लिए आसपास के इलाकों में बहुत समस्या हो रही है, तब इस द्वीप का निर्माण करवाया गया था।

मुनरो द्वीप की खासियत

केरल के साथ-साथ दक्षिण भारत का भी यह एक ऐसा आइलैंड है, जो नदी और झील के किनारे स्थित है। मुनरो द्वीप अष्टमुडी झील और कल्लदा नदी के संगम पर स्थित है। जोकि अपने आप में अनोखा है।

इस द्वीप के बारे में कहा जाता है कि यह केरल का छिपा हुआ मोती है, जो करीब 8 द्वीपों से बना हुआ है। यहां पर स्थित बैकवाटर और लैगून पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है।

सैलानियों के लिए है खास

मुनरो द्वीप अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और यहां पर हर दिन हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। खासकर जो सैलानी बैकवाटर और लैगून से प्रेम करते हैं, उनके लिए मुनरो द्वीप किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वहीं प्रकृति प्रेमियों के लिए भी यह खास जगह है।

मुनरो द्वीर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ शांत और शुद्ध वातावरण के लिए जाना जाता है। यहां पर कई पर्यटक बोटिंग का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते हैं। मानसून में इस द्वीप की खूबसूरती चरम पर होती है।

आसपास घूमने की जगहें

मुनरो द्वीप के आसपास कई शानदार और मनमोहक जगहें हैं। ऐसे में आप इन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप यहां पर अष्टमुडी झील, वेस्ट एंड ईस्ट कल्लाडा और थेवलक्करा गांव को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।

कैसे पहुंचे मुनरो द्वीप

बता दें कि मुनरो द्वीप पहुंचना आसान है। इसके पास में कोल्लम रेलवे स्टेशन है, जोकि यहां से 27 किमी दूर है। वहीं अगर आप हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं, तो यहां पर सबसे पास त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट जोकि 80 किमी दूर है। ऐसे में आप एयरपोर्ट से कैब या टैक्सी करके मुनरो द्वीप जा सकते हैं।

महाराष्ट्र का छिपा हुआ खजाना है कोयनानगर, मानसून में यहां घूमना है जन्नत के बराबर

कोयनानगर को महाराष्ट्र का छिपा हुआ खजाना माना जाता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कोयनानगर की खासियत, यहां की खूबसूरती और यहां पर मौजूद शानदार जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं।

देश के पश्चिमी भाग में स्थित महाराष्ट्र एक प्रमुख राज्य होने के साथ ही खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। यह एक ओर ऊंचे-ऊंचे पहाड़ तो दूसरी ओर अरब सागर से घिरा है। महाराष्ट्र अपनी खूबसूरती के कारण पर्यटकों के अपनी ओर आकर्षित करता है। महाराष्ट्र में कई ऐसी हसीन, ऐतिहासिक और शानदार जगहें मौजूद हैं, जहां पर घूमने के लिए दुनियाभर से लोग आते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से लेकर लोनावाला, खंडाला और माथेरान जैसी जगहों के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन यहां पर स्थित कोयनानगर के बारे में कम लोग जानते हैं। इस जगह को महाराष्ट्र का छिरा हुआ खजाना माना जाता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कोयनानगर की खासियत, यहां की खूबसूरती और यहां पर मौजूद शानदार जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं।

महाराष्ट्र में कोयनानगर

कोयनानगर महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। सतारा जिला खूबसूरत पहाड़ और झील-झरनों के लिए जाना जाता है। वहीं कोयनानगर को कोयना के नाम से भी जाना जाता है।

सतारा जिले में कोयना नदी के किनारे कोयनानगर है। यह सतारा शहर से कुछ ही दूरी पर बसा है। कोयनानगर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से करीब 294 किमी दूर है। पूणे से 190 किमी और सांगली से 130 किमी दूर है।

कोयनानगर की खासियत

कोयनानगर चिपलून-सांगली राजमार्ग पर स्थित है और यह कई चीजों के लिए फेमस माना जाता है। कोयनानगर में स्थित कोयना बांधा भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक माना जाता है।

कोयना बांध के पीछे स्थित शिवसागर जलाशय भी कोयनानगर को खास बनाने का काम करता है। यह जगह सतारा जिले के साथ ही पूरे महाराष्ट्र का छिपा हुआ खजाना माना जाता है। यहां पर आप एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं।

कोयनानगर की खूबसूरती

बता दें कि कोयनानगर को खूबसूरती का खजाना माना जाता है। यह जगह शहर की भीड़-भाड़ से दूर अपने शांत और शुद्ध वातावरण के लिए भी जाना जाता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह स्वर्ग से कम नहीं है। कोयनानगर की हरियाली यहां की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करती है।

यहां पर क्रिस्टल क्लियर झील, ऊंचे-ऊंचे पहाड़ और घने जंगल देखने को मिलेंगे। वहीं वीकेंड पर कई पर्यटक यहां पर पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। वहीं मानसून में कोयनानगर की खूबसूरती देखने लायक होती है।

कोयनानगर में घूमने की जगहें

कोयनानगर में कई शानदार और बेहतरीन जगहें हैं, जहां पर घूमने के बाद आप महाराष्ट्र की फेमस जगहों को भूल जाएंगे। यहां पर कोयना डैम, कोयना नदी, नेहरु गार्डन और कोयनानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि खूबसूरत जगहें मौजूद हैं।

कोयनानगर के आसपास कामरगांव, हूंबर्ली, वजेगांव, ओजार्डे वॉटरफॉल और कोयना बैकवाटर व्यू पॉइंट जैसी जगहों को घूम सकते हैं।

कैसे पहुंचे कोयनानगर

यहां पर पहुंचना बहुत आसान है, कोयनानगर का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पुणे है। जोकि करीब 192 किमी दूर है। वहीं कोयनानगर का नजदीकी रेलवे स्टेशन चिपलून है जो 42 किमी दूर है। पुणे से चिपलून के लिए लोकल ट्रेन आदि चलती हैं और यह शानदार जगह चिपलून-सांगली राजमार्ग पर स्थित है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

पीएम मोदी ने ऑस्ट्रियाई चांसलर से की मुलाकात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में ऑस्ट्रिया के चांसलर डॉ क्रिश्चियन स्टॉकर के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रिया के बीच आपसी रिश्तों को और मजबूत करना है। बैठक के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों (रूमह्य) पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद दोनों देश ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर के साथ संयुक्त प्रेस बयान में दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि चांसलर का यह दौरा व्यापार और निवेश में नई ऊर्जा लाएगा। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रिया मिलकर टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन को मजबूत करेंगे, ताकि दुनिया को भरोसेमंद समाधान मिल सके।

विपक्ष राज्यसभा उपसभापति के चुनाव का बहिष्कार करेगा

नईदिल्ली। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि विपक्ष राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव का बहिष्कार करेगा। यह मोदी सरकार द्वारा सात वर्षों से लोकसभा में उपसभापति नियुक्त न किए जाने के विरोध में किया जा रहा है। संचार प्रभारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सरकार ने इस मामले पर कोई सार्थक परामर्श भी नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष को उम्मीद है कि हरिवंश 3.0 उनकी मांगों के प्रति अधिक उदार और ग्रहणशील होगा। रमेश ने अपने पोस्ट में कहा कि पहली बात तो यह है कि मोदी सरकार ने सात वर्षों से लोकसभा में उपसभापति नियुक्त नहीं किया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दूसरी बात, राज्यसभा में उपसभापति का पद उपसभापति के पद के समान होता है। श्री हरिवंश का दूसरा कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हुआ। एक दिन बाद ही उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया।

गोरखपुर में अत्याधुनिक सुरक्षा भवन का योगी ने किया उद्घाटन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सुशासन के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि किसी भी राज्य की प्रगति के लिए सुरक्षा सबसे बुनियादी आवश्यकता है। गोरखपुर के श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर में एक नए और आधुनिक सुरक्षा भवन का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस सुधारों और कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर प्रदेश में आए बदलावों को विस्तार से साझा किया। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर में एक आधुनिक सुरक्षा भवन का उद्घाटन करने के बाद संबोधन में कहा, सुरक्षा सुशासन की पहली शर्त है। हर व्यक्ति को सुरक्षा की जरूरत होती है। हालांकि सरकारों ने हमेशा इस दिशा में प्रयास किए हैं, लेकिन पहले उनका ध्यान ज्यादातर सिर्फ भर्ती तक ही सीमित रहता था। योगी ने कहा कि सिर्फ कर्मियों की भर्ती करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और उचित सुविधाएं दिया जाना भी महत्वपूर्ण है।

सीएम स्टालिन ने परिसीमन बिल की कॉपी जलाई

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन के विरोध में विधेयक की प्रति जलाकर और काला झंडा फहराकर अपना विरोध और तेज कर दिया और राज्यव्यापी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की। सरकार गुरुवार से संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाएगी, जिसमें भारत की चुनावी संरचना और प्रतिनिधित्व प्रणाली को नया रूप देने वाले तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश किए जाने के कारण हंगामेदार माहौल रहने की आशंका है। काले वस्त्र पहने स्टालिन ने संविधान (एक सौ इकतीसवें संशोधन) विधेयक, 2026 के विरोध में काला झंडा फहराया, जिसमें राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के आकार और संरचना को बदलने के लिए परिसीमन का प्रस्ताव है। उन्होंने इस विधेयक की एक प्रति भी जलाई, जिसे उन्होंने काला कानून बताया। एक्स पर एक पोस्ट में, स्टालिन ने तमिलनाडु भर में व्यापक प्रतिरोध का आह्वान किया।

बिहार के चार नेताओं ने ली राज्यसभा में शपथ

पटना। शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव के जरिए निर्वाचित हुए चार नेताओं ने उच्च सदन में शपथ ली। इन चार नेताओं में दो राजनीतिक दल के प्रमुख हैं। इनमें पहला नाम है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और दूसरा नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का है। इनके अलावा तीसरा नंबर पर जनता दल यूनाईटेड के वरिष्ठ नेता रामनाथ ठाकुर। उन्हें जदयू ने फिर से राज्यसभा भेजा है। इन सांसदों के शपथ लेने के बाद बिहार भाजपा की ओर से बधाई दी गई। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बिहार से राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जदयू के वरिष्ठ नेता रामनाथ ठाकुर, प्रदेश महामंत्री शिवेश कुमार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विश्वास है कि आपके नेतृत्व में बिहार की आवाज़ संसद में और अधिक मजबूती से गूंजेगी तथा विकास की दिशा को नई गति मिलेगी।

उत्तर-दक्षिण किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा: प्रधानमंत्री मोदी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि परिसीमन प्रक्रिया में राज्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वे उत्तर, दक्षिण, बड़े या छोटे हों। परिसीमन विधेयक पर विस्तार से बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दिया कि इस प्रक्रिया का विरोध करने वाले लोग केवल राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह आश्वासन दिया कि कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा। मोदी ने महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों पर चर्चा के लिए आयोजित संसद के विशेष सत्र के दौरान कहा कुछ लोग सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आश्वस्त करना चाहता हूं कि चाहे उत्तर हो या दक्षिण, इस प्रक्रिया में किसी तरह का भेदभाव या अन्याय नहीं होगा।

इसके साथ ही मोदी ने कहा कि मैं वादा कर सकता हूं और गारंटी दे सकता हूं; अगर आप गारंटी शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं करूंगा, अगर आप वादा शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं करूंगा। उन्होंने कहा कि भूतकाल में जो सरकार रही, जिनके काल में जो परिसीमन हुआ, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा, और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी चाहिए तो मैं गारंटी देता हूं, वादा चाहिए तो वादा देता हूं... क्योंकि अगर नीयत साफ है, तो शब्दों

का खेल करने की जरूरत नहीं है।

मोदी ने कहा कि हम उस अहंकार में न रहें कि हम देश की नारी शक्ति को कुछ दे रहे हैं... जी नहीं! उसका हक ?है। हमने कई दशकों से रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित कर उस पाप से मुक्ति पाने का अवसर है। उन्होंने कहा कि यहां कुछ लोगों को लगता है कि इसमें मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन अगर साथ चलेंगे तो किसी को कोई राजनीतिक फायदा नहीं होगा। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ही ये पारित हो जाए, मैं कल विज्ञापन देकर सबका धन्यवाद करने को तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने को तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो... आपको जिसकी फोटो छपवानी है, मैं सरकारी खर्चे से छपवाने को तैयार हूं।

उन्होंने कहा कि देश में करीब 650+ जिला पंचायतें हैं। करीब पौने तीन सौ महिलाएं उसका नेतृत्व करती हैं। एक कैबिनेट मीनिस्टर से ज्यादा जिम्मेदारी होती है उन पर, काम करती हैं वो। करीब 6,700 ब्लॉक पंचायतों में से करीब 2700 से अधिक ब्लॉक पंचायतें ऐसी हैं, जिनका नेतृत्व महिलाओं के हाथ में हैं। आज देश में 900+ शहरों में अर्बन लोकल बॉडीज की हेड के रूप में बहनें कार्यरत हैं। मैं मानता हूं, आज देश जो प्रगति कर रहा है, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, इस ऋष्ण को हमें स्वीकार करना चाहिए।

हरियाणा में जनगणना 2027 का शंखनाद

ये पीएम मोदी के विकसित भारत की नींव है: नायब सिंह सैनी

नईदिल्ली। हरियाणा सरकार ने राज्यव्यापी डिजिटल स्व-गणना अभियान शुरू करके 2027 की जनगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो अधिक प्रौद्योगिकी-आधारित और पारदर्शी प्रणाली की ओर एक कदम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं अपनी स्व-गणना पूरी करके इस प्रक्रिया की शुरुआत की और इसमें जनता की भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया। स्वयं जनगणना का चरण शुरू हो चुका है और 30 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान निवासियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने परिवार की जानकारी जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

अधिकारियों ने इस पहल को महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया से कहीं अधिक बताया और इसे विकसित हरियाणा की परिकल्पना को साकार करने और विकसित भारत के व्यापक लक्ष्य में योगदान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस चरण के बाद, जनगणना का पहला औपचारिक चरण 1 से 30 मई, 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि डिजिटल उपकरणों के उपयोग से दक्षता में वृद्धि, पारदर्शिता में सुधार और प्रक्रिया को पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक नागरिक-अनुकूल बनाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना का अभ्यास महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह विकसित हरियाणा के निर्माण और विकसित भारत की परिकल्पना में योगदान देने की दिशा में एक मूलभूत कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए नागरिकों से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए देशवासियों को जनगणना में भाग लेना आवश्यक है।राज्य सरकार ने लोगों से सक्रिय रूप से भाग लेने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि प्रदान की गई सभी जानकारी सटीक हो, क्योंकि एकत्रित किए गए।

साऊथ को गारंटी- एक भी सीट कम नहीं होगी, बढ़ेगा प्रतिनिधित्व: शाह

नईदिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार (16 अप्रैल) को कहा कि यह अफवाह फैलाई जा रही है कि परिसीमन के बाद लोकसभा में दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व घट जाएगा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि वास्तव में उनकी संख्या बढ़ेगी। उनके अनुसार, लोकसभा में दक्षिणी राज्यों की संख्या बढ़कर 195 हो जाएगी। संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में बोलते हुए शाह ने कहा कि यह अफवाह फैलाई जा रही है और भ्रम पैदा किया जा रहा है कि ये तीन विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक और परिसीमन तथा चुनाव प्रक्रियाओं में बदलाव से संबंधित दो कानून, लोकसभा में दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व को कम कर देंगे और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाएंगे। सदन के समक्ष प्रस्तुत विधेयक अब सदन की संपत्ति है।

शाह ने कहा कि सीटों में समग्र वृद्धि से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी राज्य पूर्ण रूप से अपना मौजूदा प्रतिनिधित्व न खोए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य विस्तारित लोकसभा के माध्यम से जनसंख्या परिवर्तनों को समायोजित करते हुए निष्पक्षता बनाए रखना है। शाह ने कहा कि यदि हम दक्षिण के लिए बनाए गए पूरे विवरण को सुनें, तो आपके द्वारा सृजित 543 सीटों में से वर्तमान में 129 सांसद इस सदन में बैठे हैं, जो लगभग 23.76त्न है। नए सदन में 195 सांसद बैठेंगे, और उनकी शक्ति 23.97त्न होगी।शाह ने कहा कि ऐसी धारणा पैदा की जा रही है कि इन तीनों विधेयकों के पारित होने से दक्षिण राज्यों की संख्या लोकसभा में बहुत कम हो जाएगी और उन्हें बड़ा नुकसान होगा।

टीएमसी की वजह से बार्डर सुरक्षित नहीं है: हिमंत बिस्वा

नईदिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत का पूरा भरोसा जताया। उन्होंने टीएमसी सरकार पर राज्य में घुसपैठियों को घुसने देने का आरोप भी लगाया। एक जनसभा में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए, असम के मुख्यमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में घुसने से रोकने के लिए सीमाओं पर बाड़ लगाना ज़रूरी है।

उन्होंने कहा हमें असम में 100 सीटें मिलेंगी और पश्चिम बंगाल में 200 सीटें। उन्होंने आगे कहा, हमारी एकमात्र चिंता यह है कि बांग्लादेशियों को हमारे देश में घुसने की इजाज़त क्यों दी जानी चाहिए? ममता बनर्जी हमें बांग्लादेशियों को देश में घुसने से रोकने नहीं देतीं। सीमा पर बाड़ लगाना बहुत ज़रूरी है।

इसके अलावा, उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य में कथित गौ-तस्करी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सत्ता में आने के बाद भाजपा इसे रोक देगी। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा शासित राज्यों में मांस पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। उन्होंने कहा कि हर दिन, माँ कामाख्या में पशु बलि की रस्म होती है, लेकिन असम में मांस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ममता जी को डर है कि जब भाजपा सत्ता में आएगी, तो मांस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। असम और बिहार में भाजपा की सरकारें हैं, लेकिन वहाँ मांस पर प्रतिबंध नहीं है। ममता जी को डर है कि भाजपा के सत्ता में आने से, उनके राज्य में गायों की तस्करी रुक जाएगी। दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पर बंगाल की पहचान और संवैधानिक अधिकारों को कमज़ोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। साथ ही, उन्होंने कहा कि उन्होंने पोइला बोइशाख पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच बिताया और राज्य की सेवा करने के अपने संकल्प को दोहराया।

खेल
प्रमुख समाचार

धोनी 23 को मुंबई इंडियंस के खिलाफ वापसी कर सकते हैं

मुम्बई। चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी अब पिंडली में आये खिंचाव से उबर गये हैं और उनकी शीघ्र टीम में वापसी की संभावनाएं हैं। धोनी की कमी टीम को काफी महसूस हो रही है पर अब क्रिकेट प्रेमियों और प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर है। एक रिपोर्ट के अनुसार धोनी 23 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल मैच से वापसी कर सकते हैं। धोनी को इस मैच में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उतारा जा सकता है।

धोनी अभ्यास सत्र दौरान पिंडली में खिंचाव के कारण शुरुआती मैचों से बाहर हो गए थे। हालांकि, अब रिपोर्टों के मुताबिक 44 वर्षीय धोनी अब पूरी तरह से फिट होने के करीब हैं। धोनी के नहीं खेलने पर सीएसके का अब तक का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। टीम ने आईपीएल 2024 में पांच मुकाबले खेले हैं, जिनमें से तीन में उसे हार का सामना करना पड़ा और दो में जीत मिली। शुरुआती तीन हार के बाद, ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली टीम ने पिछले दो घरेलू मैचों में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर अपनी लय हासिल कर ली है। हालांकि, मौजूदा अंक तालिका में सीएसके 10 टीमों में से आठवें स्थान पर है, ऐसे में टीम को धोनी की वापसी का बेसब्री से इंतजार है ताकि टीम और बेहतर प्रदर्शन कर सके। अधिक बोझ न डालते हुए टीम धोनी को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान पर उतार सकती है, जिससे उनकी बल्लेबाजी का पूरा लाभ उठाया जा सके। धोनी के होने भर से ही टीम में उत्साह रहता है। इसके अलावा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को भी वह जरुरी सलाह दे सकते हैं।

धोनी के लिए मुंबई इंडियंस के खिलाफ वापसी करना एक विशेष क्षण होगा, क्योंकि इस टीम के खिलाफ उनका रिकॉर्ड हमेशा शानदार रहा है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 122 अंक टूटा निफ्टी 24196 पर बंद

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों से पॉजिटिव संकेत लेते हुए भारतीय शेयर बाजार गुरुवार (16 अप्रैल) को मजबूती के साथ खुले। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने का निवेशकों के सेंटीमेंट्स पर सकारात्मक असर पड़ा और बाजार मजबूती के साथ खुला और बाजार उतार-चढ़ाव के बीच गिरावट में बंद हुए। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 78,677 अंक पर खुला। बुधवार को यह 78,111 पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान यह 78,730 अंक तक चढ़ गया था लेकिन अंत में 122.56 अंक या 0.16 फीसदी की गिरावट लेकर 77,988.68 पर बंद हुआ। इसी तरह, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी मजबूती के साथ 24,385 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान यह 24,400.95 अंक के इंट्रा-डे हाई तक गया। अंत में 34.55 अंक या 0.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,196 पर बंद हुआ।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर एनपीओ के लिए नियमों में ढील

नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) को बढ़ावा देने के लिए कई अहम सुधार लागू किए हैं। बुधवार को जारी एक सर्कुलर में, सेबी ने नॉट-फॉर-प्रॉफिट संगठनों (एनपीओ) के लिए रजिस्ट्रेशन की वैधता बढ़ाने और फंड जुटाने की शर्तों को आसान बनाने की घोषणा की है। इन कदमों का मुख्य उद्देश्य बाजार में सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाना और उनके लिए धन जुटाने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। नियामक ने बिना फंड जुटाए सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर पंजीकृत रहने की सीमा को बढ़ा दिया है। पहले यह सीमा दो साल थी, जिसे अब बढ़ाकर अधिकतम तीन साल कर दिया गया है। नए नियमों के अनुसार, कोई भी एनपीओ पंजीकरण की तारीख से दो साल तक बिना फंड जुटाए एक्सचेंज पर पंजीकृत रह सकता है।

आईसीआईसीआई की इंश्योरेंस कंपनी दे सकती है अच्छी रिटर्न

नई दिल्ली। आईसीआईसीआई ग्रुप की जनरल इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के शेयर गुरुवार (16 अप्रैल) को शुरूआती कारोबार में 3 फीसदी के करीब चढ़ गए। कंपनी के शेयरों में यह तेजी एक दिन पहले जारी किए गए तिमाही नतीजों के चलते देखने को मिली। हालांकि, कंपनी ने 31 मार्च को समाप्त तिमाही में उम्मीद से कमजोर वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में शुद्ध मुनाफे में 7.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की और यह 547 करोड़ रुपये रहा। इस बीच, ज्यादातर ब्रोकरेज बीमा कंपनी को लेकर सकारात्मक बने हुए हैं और उन्होंने शेयर पर 2,350 रुपये तक के टारगेट प्राइस दिए हैं, जो मौजूदा स्तर से 26 प्रतिशत से अधिक की संभावित बढ़त का संकेत देता है।

कोयला मंत्रालय आज शुरू करेगा खदानों की नीलामी

नई दिल्ली। भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से कोयला मंत्रालय शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026 को वाणिज्यिक कोयला खदानों की 15वीं नीलामी प्रक्रिया का शुभारंभ करने जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत: ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोयला विषय पर आधारित इस कार्यक्रम की शुरुआत मुंबई में एक महत्वपूर्ण हितधारक परामर्श बैठक के साथ होगी। मुंबई में होने वाली यह परामर्श बैठक उद्योग जगत की कंपनियों, निवेशकों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगी जहां नीलामी की प्रक्रियाओं, खनन सुधारों एवं वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक ढांचे में मौजूद अवसरों पर चर्चा की जाएगी।

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें आम आदमी की जेब पर भारी संकट

कांतिलाल मांडोत

देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर एक बार फिर चिंता गहराती नजर आ रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के कारण भारत में भी ईंधन महंगा होने की आशंका बढ़ गई है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट के अनुसार, पेट्रोल की कीमतों में लगभग 18 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 35 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी संभव है। यह संभावित वृद्धि ऐसे समय में सामने आई है जब देश के कई राज्यों में चुनावी माहौल है और फिलहाल कीमतों को स्थिर रखा गया है।

भारत जैसे देश में जहां ऊर्जा की जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर करता है, वहां कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव सीधे आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 88 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व और रूस जैसे क्षेत्रों से आता है। ऐसे में वैश्विक राजनीतिक तनाव, युद्ध या आपूर्ति में कमी का असर सीधे भारतीय बाजार पर पड़ता है।

पिछले कुछ हफ्तों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। करीब डेढ़ महीने के भीतर ही कीमतों में 27 डॉलर प्रति बैरल तक का उछाल दर्ज किया गया है। इस बढ़ोतरी ने तेल कंपनियों पर भारी दबाव बना दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, तेल कंपनियां हर लीटर पेट्रोल पर करीब 18 रुपए और डीजल पर 35 रुपए तक का नुकसान झेल रही हैं। कुल मिलाकर यह नुकसान प्रतिदिन लगभग 1600 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पहले 2400 करोड़ रुपए के स्तर तक भी जा चुका था।

सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कुछ कटौती किए जाने के बावजूद यह राहत पर्याप्त

साबित नहीं हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार का तेल पर मिलने वाला राजस्व भी घटा है। जहां 2017 में यह 22 प्रतिशत था, वहीं अब घटकर करीब 8 प्रतिशत रह गया है। इसका मतलब यह है कि सरकार के पास भी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सीमित विकल्प बचे हैं। यदि सरकार पूरी तरह से एक्साइज ड्यूटी हटा भी दे, तब भी कंपनियों के घाटे की पूरी भरपाई संभव नहीं है।

इस स्थिति का एक बड़ा कारण वैश्विक स्तर पर बढ़ता तनाव भी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष, विशेष रूप से ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच बढ़ती खींचतान, कच्चे तेल की आपूर्ति को प्रभावित कर रही है। आपूर्ति में कमी और मांग में स्थिरता या वृद्धि के कारण कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं। इसका असर केवल ईंधन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।

ईंधन की कीमतें बढ़ने का सीधा असर परिवहन लागत पर पड़ता है, जिससे हर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। खाद्य तेल, साबुन, शैंपू, बिस्किट और अन्य रोजमर्रा के उत्पाद महंगे होने लगते हैं। कई कंपनियां कीमतें बढ़ाने के बजाय पैकेट का आकार छोटा कर देती हैं, जिसे 'श्रिंकफ्लेशन' कहा जाता है। इससे उपभोक्ताओं पर अप्रत्यक्ष रूप से बोझ बढ़ता है। खाद्य तेल की बात करें तो भारत अपनी जरूरत का लगभग 57 प्रतिशत आयात करता है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से इनके दाम भी 7 प्रतिशत तक बढ़ चुके हैं। वहीं प्लास्टिक और पैकेजिंग सामग्री महंगी होने से एफएमसीजी कंपनियों की लागत बढ़ गई है। इसका असर सीधे उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है। घरेलू उपकरणों के क्षेत्र में भी लागत में 10 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि हो चुकी है। कंपनियां इसका बड़ा हिस्सा पहले ही ग्राहकों पर डाल चुकी हैं और आगे भी कीमतें बढ़ने की संभावना बनी हुई है। कपड़ा उद्योग में सिंथेटिक फाइबर की कीमतें 20 से 25 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं, जिससे कपड़ों के दाम भी बढ़ेंगे। पेंट उद्योग में भी लागत में वृद्धि के कारण 2 से 5 प्रतिशत तक कीमत बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इस पूरी स्थिति का एक और महत्वपूर्ण पहलू देश का चालू खाता घाटा है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भारत का चालू खाता घाटा बढ़ सकता है। अनुमान है कि 2026 की पहली तिमाही में यह 20 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यह देश की आर्थिक स्थिरता के लिए चिंता का विषय है।

युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री साय

■ **छत्तीसगढ़ के 430 युवाओं को मिला शासकीय सेवा का अवसर, प्रयोगशाला परिचारकों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र**

रायपुर। छत्तीसगढ़ में युवाओं के सशक्त भविष्य और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में आयोजित गरिमामय समारोह में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत चयनित 430 प्रयोगशाला परिचारकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष और व्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक सुधार किए गए हैं, जिनका सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन में शुचिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'सुशासन एवं अभिसरण विभाग' का गठन किया गया है तथा मंत्रालय के कार्यों को ई-प्रणाली से जोड़ा गया है, जिससे भ्रष्टाचार के रास्तों को प्रभावी रूप से बंद किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पूर्व में हुए पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपकर सरकार ने यह संदेश दिया है कि पारदर्शिता और न्याय सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ ही भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए कड़े कानूनी प्रावधान किए गए हैं, जिससे परीक्षाओं की विश्वसनीयता और अधिक मजबूत होगी उन्होंने आगे कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं को सरल और सुलभ बनाने के लिए 'छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल' के गठन तथा एक निश्चित 'परीक्षा कैलेंडर' लागू करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की नई औद्योगिक नीति के माध्यम से निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। उद्योगों को प्रोत्साहन देकर रोजगार सृजन को गति दी जा रही है, ताकि सरकारी नौकरियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र भी युवाओं के लिए सशक्त विकल्प बन सके।मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त कर्मचारियों से निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि वे विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने इस भर्ती प्रक्रिया को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुशासन के सिद्धांतों पर आधारित रही है। उन्होंने कहा कि योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं को उनका अधिकार दिलाने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक पहल है। मंत्री श्री वर्मा ने बताया कि पदस्थापना प्रक्रिया में भी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए काउंसलिंग प्रणाली अपनाई गई। यह व्यवस्था सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह नई पीढ़ी छत्तीसगढ़ को प्रगति और समृद्धि के नए आयामों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हाल ही में लैब टेक्नीशियन और अब प्रयोगशाला परिचारकों की नियुक्तियाँ इस दिशा में सरकार की सक्रियता का स्पष्ट प्रमाण हैं।

संविधान के मूल्यों को याद रखना होगा लिया संकल्प

रायपुर।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के शंकरनगर स्थित दुर्गा मैदान में डॉ. भीमराव आंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ भाजपा जिला रायपुर द्वारा आयोजित समरसता भोज कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने जनप्रतिनिधियों और आमजन के साथ बैठकर भोजन किया तथा स्वयं लोगों को भोजन परोसकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया । मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसके संविधान का निर्माण करने का गौरव बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर को प्राप्त है। उन्होंने कहा कि यह संविधान देश के 140 करोड़ नागरिकों को समानता, अधिकार और गरिमा के साथ जीवन जीने का आधार प्रदान करता है। इस अवसर पर मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा समरसता भोज जैसे आयोजन सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक किरण सिंह देव ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने की मजबूत व्यवस्था दी। आयोजन की प्रसंशा करते हुए प्रदेशाध्यक्ष ने कहा यह प्रदेश का पहला और बहुत भव्य आयोजन है इसके लिए उन्होंने झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक संजू नारायण सिंह एवं जिला संयोजक बृजेश अग्रवाल को साधुवाद दिया। समरसता भोज कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडेय , अखिलेश सोनी, विधायक पुरंदर मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर, महामंत्री अमित मैशेरी ,गुंजन प्रजापति, उपाध्यक्ष अकबर अली, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा, प्रकोष्ठ सहसंयोजक , अजीत सेनापति जी राजेश रिछारिया, रोहित राय ,शंकर नगर मंडल अध्यक्ष राम प्रजापति, मंडल मंत्री राम तांडी , संदीप सोनी, राज सोना, जगन्नाथ जाल श्याम यादव, भवानी कुमार, किशोर बघेल, किशोर दीप, इंद्र नायक सौम्य त्रिपाठी ,उपेंद्र साहू ,देवेंद्र बाग ,गोपाल बाग अभिषेक टांडी , नदीम भाई मोंटू आदि उपस्थित थे।

मजदूरों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देने से दुर्घटनाएं हो रही : चरणदास महंत

रायपुर। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की अगुवाई में सक्ती के वेदांता पावर प्लांट गया तथा दुर्घटना स्थल एवं प्रभावितों से मुलाकात किया। उनके साथ वेदांता पावर दुर्घटना के लिए बनाई गई कांग्रेस की जांच समिति के संयोजक जयसिंह अग्रवाल एवं सदस्यगण पूर्व मंत्री उमेश पटेल, पूर्व मंत्री नोबेल वर्मा, विधायक रामकुमार यादव, उत्तरी जांगड़े, अटल श्रीवास्तव, बालेश्वर साहू, राघवेन्द्र सिंह, व्यास कश्यप, शेषराज हरवंश, जिला अध्यक्ष रश्मि गबेल, राजेश अग्रवाल भी शामिल हुए।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में लगातार हो रही औद्योगिक दुर्घटनाएं चिंता का विषय है। यह सुरक्षा मानकों के प्रति बरती जा रही घोर लापरवाही है। ऐसी घटना केवल दुर्घटना नहीं हत्या है, सदोष मानव वध है। राज्य में पिछले ढाई सालों में औद्योगिक दुर्घटना में लगभग 300 श्रमिकों की जानें गयी है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि घटना के लिए प्रबंधन की जवाबदेही तय कर मुकदमा दर्ज किया जाए। सरकार प्रबंधन को बचा देती है इसीलिए घटना की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है। हर बार सरकार प्रबंधन को बचाने का काम करती है। हमारी मांग है ऐसी कार्यवाही हो ताकि सुरक्षा मानकों के लिए लापरवाही बंद हो।

घायलों का समुचित इलाज होना चाहिए। मृतकों को 1 करोड़, घायलों को 50 लाख मुआवजा दे। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि भाजपा की सरकार में छत्तीसगढ़ में औद्योगिक सुरक्षा की स्थिति भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, मजदूरों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देने से दुर्घटनाएं हो रही। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि भट्टी बंद किए, बिना ही जोखिम भरे काम करवाना, सुरक्षा उपकरणों का न होना और बिना उचित परमिट के काम करना सामान्य बात हो गई है जो सुरक्षा तंत्र की विफलता का स्पष्ट संकेत है।

भीषण गर्मी को देखते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश में संशोधन

अब 20 अप्रैल से 15 जून तक रहेगा स्कूलों में अवकाश

रायपुर। प्रदेश में बढ़ती भीषण गर्मी और लू के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्कूलों के ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में आंशिक संशोधन किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि बढ़ती भीषण गर्मी में बच्चों की सेहत की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित करना हम सब की जिम्मेदारी है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूर्व निर्धारित ग्रीष्मकालीन अवकाश को पहले लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि इस भीषण गर्मी में बच्चों की सेहत सुरक्षित रह सके।

स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पूर्व में दिनांक 01 मई 2026 से 15 जून 2026 तक घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश में संशोधन करते हुए अब दिनांक 20 अप्रैल 2026 से 15 जून 2026 तक अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश प्रदेश के समस्त शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त एवं अशासकीय शालाओं पर लागू होगा।

मुख्य सचिव विकासशील ने भी स्व-गणना के तहत अपनी जानकारी दर्ज की

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के तारतम्य में 16 से 30 अप्रैल 2026 तक स्व-गणना की प्रक्रिया की शुरूआत हुई है। आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील ने स्व-गणना के तहत स्वयं अपनी जानकारी दर्ज की। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगुआ, छत्तीसगढ़ जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल सहित जनगणना निदेशालय के अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्य सचिव ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि इस सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें और अपनी जानकारी स्वयं भरकर जनगणना में सक्रिय भागीदारी निभाएं। राज्य में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक नागरिकों को स्व-गणना के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज करने का अवसर दिया गया है। आज अपर मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगुआ ने भी स्व-जनगणना के तहत अपनी जानकारी पोर्टल पर जानकारी दर्ज की। स्व-गणना के लिए ह्वट्टह्यद्ध.द्गठ्ठह्यह्वह्य.द्दश1.द्बठ्ठ पोर्टल पर जाकर आसानी से विवरण भरा जा सकता है।

मुख्य सचिव ने कहा है कि यह पहल जनगणना प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और अधिक विश्वसनीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे लोग अपनी सही और पूरी जानकारी स्वयं साझा कर सकेंगे। स्व-गणना अवधि समाप्त होने के बाद, 1 मई से 30 मई तक जनगणना टीम घर-घर जाकर लोगों से जानकारी एकत्रित करेगी। प्रगणक घर-घर आकर जानकारी दर्ज करेंगे। हर मकान की जानकारी दर्ज की जाएगी।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

मोदी सरकार परिसीमन को इससे अलग रखेः दीपक बैज

रायपुर। कांग्रेस शुरू से महिला आरक्षण बिल की समर्थक रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक 2010 में राज्यसभा में पारित कराया था। कांग्रेस ने 2023 में भी महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया था, आज भी हम समर्थन में है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन में महिलाओं को धोखा दे रही है। आज जो परिस्थितियां है वह सही मायने में आरक्षण के लक्ष्य को पूरा नहीं करेंगी। कांग्रेस पार्टी मांग करती है पहले जनगणना हो, फिर परिसीमन हो, उसके बाद महिला आरक्षण बिल पास हो ताकि देश के सभी राज्यों के छोटे-बड़े राज्यों सभी के साथ न्याय हो। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या के आधार पर ही आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा से आधी आबादी को उसका पूरा अधिकार देने की पक्षधर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल लाने के लिये प्रधानमंत्री मोदी से बात किया था। कांग्रेस की सरकारों ने समय-समय पर इस हेतु प्रभावी कदम भी उठाया है। सबसे पहले राजीव गांधी ने 1989 के मई महीने में पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के एक तिहाई आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया।

सरकार किस बात का सुशासन तिहार मनाने जा रही हैः शुक्ला

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि साय सरकार किस बात का सुशासन तिहार मनाने जा रही है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, आत्मानंद स्कूलों में स्टेशनरी तक नहीं, आरटीई में बच्चों को एडमिशन नहीं हो रहा, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा, राज्य की कानून व्यवस्था समाप्त हो गयी है। मासूम बच्ची के साथ दुराचार करके हत्या कर दी जाती है। राज्य में रोज हत्या, डकैती, बलात्कार हो रहा है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार में धान घोटाला हो जाता है। महिलाओं को घटिया साड़ी दी जाती है। आत्ममुग्ध सरकार सुशासन तिहार मना रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सुशासन का दंभ भरने वाली साय सरकार के राज में आम आदमी छोटे-छोटे काम के लिये सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटने को मजबूर है। पटवारी कार्यालय से लेकर तहसील दफ्तरों में लोगो के नामांतरण, फौत, त्रुटि सुधार के लाखो आवेदन लंबित है, लोगों के काम नहीं हो रहे, आम आदमी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर है। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि लाखों लोगों को सरकार के पास सड़क, नाली, बिजली, पानी जैसे रोजमर्रा के कामो के लिये आवेदन देने सरकार के सुशासन तिहार का इंतजार करना पड़ता है।

सरकार को शराब दुकान खोलने जगह कम पड़ रहीः ठाकुर

रायपुर। राजनांदगांव के घुमका गौठान में शराब दुकान खोलने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार को शराब दुकान खोलने जगह कम पड़ रही है तो उन्हें आबकारी मंत्री के सरकारी बंगला और भाजपा कार्यालयों में दुकान खोलना चाहिये, कम से कम गोठनों को छोड़ देते। गौठान में शराब दुकान खोलना क्या यही भाजपा की गौ सेवा है? गौठान जहाँ कांग्रेस सरकार में पशुधन संरक्षण नस्ल सुधार दुग्ध उत्पादन का केंद्र था। भाजपा उन गौठानो के खिलाफ हमेशा रही है, विपक्ष में रहते गौठानो के खिलाफ दुष्प्रचार किया और सत्ता मिलते ही गोठनों में तालाबंदी कर पशुधन को खदेड़ा दिया। अब गोठनों में शराब दुकान खोलकर अपनी मदिरा प्रेम को प्रदर्शित कर रही है, यही भाजपा का असली चरित्र है। भाजपा सरकार की शराब की कमाई की भूख ने गौ धन को भी सड़को में भटकने भूखे मरने दुर्घटना का शिकार होने मजबूर कर दिया है।भाजपा चुनावी गौ सेवक है वोट के लिए गौ माता की जयकारा लगाती है और सत्ता मिलने पर बीफ कम्पनियों से करोड़ो रुपया चंदा लेती है। ढाई साल की सरकार में प्रदेश में गौ तस्करी बढ़ी है दुर्घटनाओं में हजारों पशुधन की मौत हुई है।

सत्ता के संरक्षण में शराब गली-गली में बिक रहीः वंदना

रायपुर। महासमुंद के पटेवा थाना में अवैध शराब विक्रेताओं को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला बेहद चिंता का विषय है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि प्रदेश सत्ता के संरक्षण में अवैध शराब और नशा का कारोबार इतना बढ़ गया है कि अपराधी इतने सांठगांठ नहीं करने वाले पुलिस वालों को धमकाने, मारपीट करने से भी पीछे नहीं हटते। महासमुंद की घटना में टीआई सहित पांच पुलिस वालों पर प्राण घातक हमला हुआ, सभी गंभीर रूप से घायल हो गये। बताया जाता है कि अवैध शराब बेचने वालों को सत्तारूढ़ दल के स्थानीय नेताओं का संरक्षण मिला हुआ है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि राज्य में जब से भाजपा की सरकार बनी है। छत्तीसगढ़ अवैध शराब का गढ़ बन गया है। साय सरकार शराब की काली कमाई में डूबी हुई है।सरकारी वाहनों और सरकारी अमला शराब तस्करी करवाता है। राजनांदगांव में महतारी एक्सप्रेस का उपयोग शराब तस्करी के लिए किया जा रहा था। मुंगेली में स्कूल को अवैध शराब का डंप यार्ड बना दिया गया। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा, राजनांदगांव सहित प्रदेश के सभी शहरों में नकली होलो ग्राम लगा कर अवैध शराब बेची जा रही।

नकली पनीर सरकार की चुप्पी चुभने वाली है : वर्मा

रायपुर। कांग्रेस ने नकली पनीर पर सरकार के रवैये पर आक्रोश व्यक्त किया है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि सरकार की नाक के नीचे नागरिकों की मौत का सामान बिक रहा है। राजधानी सहित पूरे प्रदेश में पकड़ा रही नकली पनीर पकड़ाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, खाद्य मंत्री की चुप्पी नागरिकों को परेशान करने वाली है। यह सामान्य बात नहीं है कि राज्य की राजधानी में सरकार की नाक के नीचे सबसे लोकप्रिय खाद्य सामग्री बड़ी मात्रा में बनाया जा रहा और खपाया जा रहा, सरकार के जिम्मेदार मौन है। यह सरकार के खाद्य एवं औषधि विभाग की लापरवाही है कि लगातार प्रदेश में नकली पनीर खुलेआम बन रही है और बिक रही है। जानवरो की चर्बी और तेल तथा सोडे से पनीर बनाया जा रहा, सरकार क्या रही है? कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि नकली पनीर के निर्माण और बिक्री पर रोकथाम के लिये सरकार विशेष दल का गठन करें और प्रदेश के किसी भी कोने में बन रही नकली खाद्य सामग्री पर कड़ाई से रोक लगाई जाये। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि ने कहा कि भाजपा के कुशासन में आम जनता की सेहत भगवान भरोसे है।

अब नागरिक खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी

जनगणना 2027 के तहत स्व-गणना की शुरूआत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के तारतम्य में 16 से 30 अप्रैल 2026 तक स्व-गणना की प्रक्रिया की शुरूआत हुई है। आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील ने स्व-गणना के तहत स्वयं अपनी जानकारी दर्ज की। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगुआ, छत्तीसगढ़ जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल सहित जनगणना निदेशालय के अधिकारी भी मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि इस सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें और अपनी जानकारी स्वयं भरकर जनगणना में सक्रिय भागीदारी निभाएं। राज्य में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक नागरिकों को स्व-गणना के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज करने का अवसर दिया गया है। आज अपर मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगुआ ने भी स्व-जनगणना के तहत अपनी जानकारी पोर्टल पर जानकारी दर्ज की। स्व-गणना के लिए https://se.census.gov.in/ पोर्टल पर जाकर आसानी से विवरण भरा जा सकता है।

मुख्य सचिव ने कहा है कि यह पहल जनगणना प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और अधिक विश्वसनीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे लोग अपनी सही और पूरी जानकारी स्वयं साझा कर सकेंगे। स्व-गणना अवधि समाप्त होने के बाद, 1 मई से 30 मई तक जनगणना टीम घर-घर जाकर लोगों से जानकारी एकत्रित करेगी। प्रगणक घर-घर आकर जानकारी दर्ज करेंगे। हर मकान की जानकारी दर्ज की जाएगी। इसमें मकान की स्थिति, सुविधाओं और मूलभूत जानकारी संकलित की जाएगी। जिन्होंने स्व-गणना के तहत जानकारी दर्ज की है वे जनगणना प्रगणकों के घर आने पर उनसे स्व ड्डट्ठ जरूर साझा करें। यदि कोई स्व-गणना नहीं कर पाते है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है।

छत्तीसगढ़ राज्य में 1 मई से 30 मई 2026 तक की अवधि में प्रगणक आपके घर आकर जानकारी अवश्य दर्ज करेंगे। सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस अवसर पर जनगणना निदेशालय के संयुक्त संचालक प्रदीप साव सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए।

नारी का सम्मान ही राष्ट्र के उत्थान का आधार है : राजेश अग्रवाल

रायपुर। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने आज पी.जी. कॉलेज अंबिकापुर के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में सहभागिता करते हुए कहा कि नारी का सम्मान ही राष्ट्र के उत्थान का आधार है। उन्होंने कहा कि आज का भारत महिलाओं को केवल सम्मान ही नहीं, बल्कि नेतृत्व और निर्णय लेने की शक्ति भी प्रदान कर रहा है, जो देश के समग्र विकास के लिए आवश्यक है।

इस अवसर पर मंत्री अग्रवाल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव वाला कदम बताते हुए कहा कि यह अधिनियम संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि इस प्रावधान से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी और नीति-निर्माण में उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित होगी, जिससे लोकतंत्र और अधिक सशक्त बनेगा।

उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। यह अधिनियम 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को मजबूती प्रदान करने के साथ ही समाज में लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देगा।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.